www.raceias.com

RACE IAS

# करेंट अफेयर्स

अगस्त, 2025 | ₹ 60/-

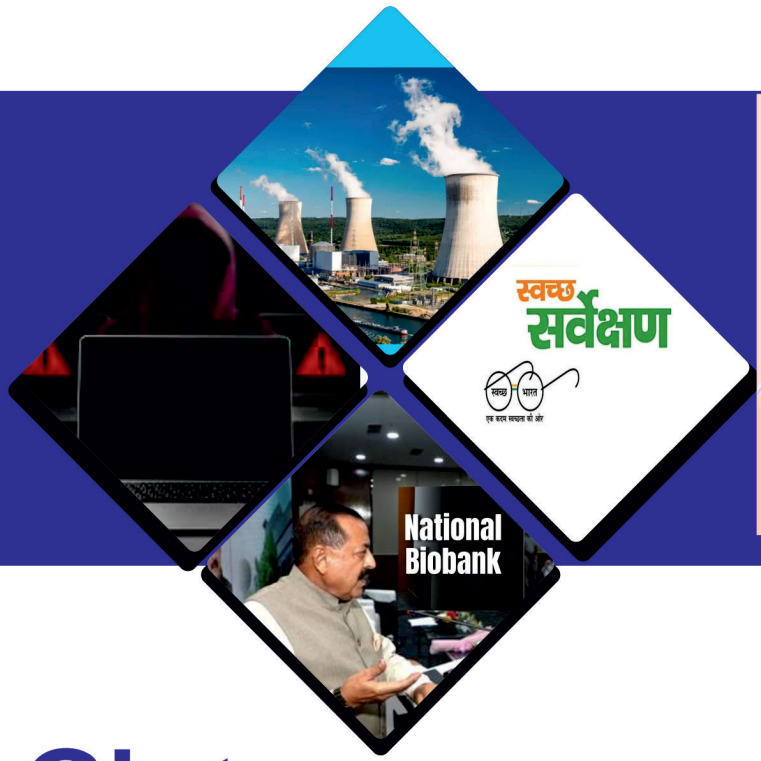

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा
अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी







50 प्रारम्भिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्न

Gist of

THE HINDU | pib | The Indian EXPRESS | Kurukshetra | YOJANA


Raghav Publication House

# RACE IAS

## UPPCS 2025
## PRELIMS TEST SERIES (PTS)

Available in हिंदी माध्यम/English Medium | Mode: Offline/Online

*Commencing from*

**5th July, 2025**

PROGRAM

**UP-PTS-2025 BATCH-01**

05 July, 2025- GS Full Length
12 July, 2025- GS Full Length
19 July, 2025- GS Full Length
26 July, 2025- GS Full Length
02 Aug., 2025- CSAT

Timing 12:00 to 2:00 pm
Offline Fees ₹ 999
Online Fees ₹ 499

**UP-PTS-2025 BATCH-02**

07 Aug., 2025- GS Full Length
13 Aug., 2025- GS Full Length
16 Aug., 2025- CSAT
23 Aug., 2025- GS Full Length
30 Aug., 2025- GS Full Length

Timing 12:00 to 2:00 pm
Offline Fees ₹ 999
Online Fees ₹ 499

**UP-PTS-2025 BATCH-03**

06 Sep., 2025- GS Full Length
13 Sep., 2025- GS Full Length
20 Sep., 2025- GS Full Length
27 sep., 2025- GS Full Length
30 Sep., 2025- CSAT

Timing 12:00 to 2:00 pm
Offline Fees ₹ 999
Online Fees ₹ 499

## KEY FEATURES:

1. Questions are designed strictly in line with the latest UPPCS pattern.
2. Detailed solutions/ explanations for all the test papers.
3. Time bound evaluation and performance assessment.

| TESTS | OFFLINE FEE | ONLINE FEE |
|---|---|---|
| General Studies Paper I<br>General Studies Paper II (CSAT)<br>Total Test = 15 | ₹ 2,499<br>(including GST) | ₹ 1,299<br>(including GST) |

**Offline Test Center:** LUCKNOW & KANPUR

| ALIGANJ | INDIRA NAGAR | ALAMBAGH | KANPUR |
|---|---|---|---|
| 7388114444 | 9044137462 | 8917851448 | 9044327779 |

# INDEX


रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना ---------- 1
डिजिटल रूप से प्रमाणित गोद लेना ---------- 2
अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना ---------- 3
भारत में असमानता ---------- 4
भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक ---------- 4
एंटी-डंपिंग शुल्क ---------- 6
भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) ----------7
नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना ---------- 8
डार्क वेब ----------9
भारत में क्षय रोग का बोझ ----------10
व्यापार: भारत, अमेरिका और रूस ---------- 11
हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ----------12
भारत में असमानता ---------- ---------- 14
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 ----------15
रशियन सेंक्शंस एक्ट, 2025 ----------16
भारत में दहेज मृत्यु ---------- 17
ब्लैक होल विलय GW231123 ---------- 17
बोलीविया- भारत ----------18
डीफाल्सीवैक्स: भारत का मलेरिया कवच ------ ----------19
परमाणु ऊर्जा विजन 2047 ---------- 20
यूनेस्को और संयुक्त राज्य अमेरिका ---------- 22
भारत-ब्रिटेन ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए ---------- ----------23
राष्ट्रीय सहकारी नीति – 2025 ---------- 24
नदियों को आपस में जोड़ना ---------- 25
महिला शतरंज विश्व कप ---------- 25
चोल साम्राज्य ---------- 26
सोहराई कला ----------26
अमेरिका ने भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाया ---------- 27
क्लुचेव्स्कॉय ज्वालामुखी ----------27
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 ---------- ----------28
**करेंट अफेयर्स (MCQ) अभ्यास सेट ----------30**


RACE IAS

# करेंट अफेयर्स

## रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना

**प्रसंग**

बेरोजगारी को दूर करने और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अगस्त 2025 से **रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना** की शुरुआत बड़े वित्तीय सहयोग के साथ की है।

**समाचार के बारे में**

• यह पहल सरकार द्वारा **केंद्रीय बजट 2024–25** के अंतर्गत लक्षित प्रोत्साहनों के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए शुरू की गई।

• ELI योजना का उद्देश्य विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित करना है।

• यह योजना उद्देश्य में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना के समान है।

• इसका लक्ष्य 1.92 करोड़ प्रथम-बार औपचारिक रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है।

**योजना की प्रमुख विशेषताएं**

• **पात्रता**: केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए जो पहली बार नौकरी में हों, जिनका वेतन ₹1 लाख/माह तक हो और जो EPFO में पंजीकृत हों।

→ अनौपचारिक से औपचारिक रोजगार की ओर स्थानांतरण को प्रोत्साहन।

• **समयावधि**: योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी।

→ दो वर्षों की निर्धारित प्रोत्साहन अवधि।

• **प्रत्यक्ष वेतन सहायता**: कर्मचारियों को किश्तों में ₹15,000 तक की प्रारंभिक वित्तीय सहायता मिलेगी।

→ औपचारिक कार्य शुरू करने की लागत को कम करने में मदद।

• **EPFO योगदान सहायता**: सरकार 4 वर्षों तक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का EPF हिस्सा वहन करेगी।

→ नियोक्ताओं पर दीर्घकालिक बोझ को कम करना।

• **नियोक्ताओं के लिए भर्ती प्रोत्साहन**: ₹1 लाख/माह वेतन पर नियुक्ति करने वाले फर्मों को प्रति कर्मचारी ₹3,000 दिए जाएंगे।
→ कंपनियों को कार्यबल विस्तार के लिए प्रेरित करना।

• **अतिरिक्त कार्यक्रम**: कौशल प्रशिक्षण और इंटर्नशिप योजनाएं कार्यबल की तैयारी में सहायक होंगी।

→ युवाओं को औपचारिक नौकरियों के लिए तैयार करना।

**योजना का महत्व**

• यह योजना केवल वेतन सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार को औपचारिक रूप देने और कौशल विकास का प्रयास भी है।

• EPFO पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर यह योजना असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाती है।

• वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर यह योजना निम्न-आय वर्ग के दीर्घकालिक समावेश को सक्षम बनाती है।

• उद्योग संघों ने इसे श्रम बाज़ार में समावेशी और संरचित सुधारों की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है।

• विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रोत्साहनों से जुड़े औपचारिक रोजगार मॉडल की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाती है।

**चुनौतियाँ**

• **प्रथम-बार कर्मचारियों की पहचान**: पूर्व अनौपचारिक रोजगार का रिकॉर्ड ट्रैक करना कठिन है।

→ उदाहरण: किसी संविदा कर्मचारी का EPF रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी वह पात्र प्रतीत हो सकता है।

• **छोटे उद्यमों में कार्यान्वयन**: छोटे फर्म EPFO में पंजीकरण नहीं कराते हैं।

→ उदाहरण: ग्रामीण क्षेत्रों के MSME औपचारिक प्रक्रिया से बचते हैं।

• **बजट उपयोग की निगरानी**: ₹99,000 करोड़ की प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करना जटिल है।

→ उदाहरण: लाभ दोहराव या धोखाधड़ी का जोखिम।

• **रोजगार की स्थिरता**: प्रोत्साहन समाप्त होने पर कर्मचारी नौकरी छोड़ सकते हैं।

→ उदाहरण: कर्मचारी वेतन सहायता पाने के बाद नौकरी बदल सकते हैं।

**आगे का रास्ता**

• **EPFO को आधार से जोड़कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।**
→ उदाहरण: एकल EPF नंबर लाभ दोहराव से रोकने में मदद करता है।

• **MSME के लिए पंजीकरण और अनुपालन लाभ पर जागरूकता अभियान चलाएं।**

RACE IAS

→ उदाहरण: द्वितीय श्रेणी के शहरों में EPFO पंजीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।

**• फंड वितरण की जिम्मेदारी तय करने हेतु थर्ड-पार्टी ऑडिट हो।**

→ उदाहरण: स्वतंत्र एजेंसियां जाँच करें कि भर्ती वास्तव में हुई या नहीं।

**• स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कौशल और भर्ती को जोड़ा जाए।**

→ उदाहरण: 'स्किल इंडिया' से प्रशिक्षित इंटर्न को ELI के तहत नियुक्त किया जाए।

**निष्कर्ष**

ELI योजना भारत के औपचारिक रोजगार तंत्र को सशक्त बनाने की एक समयानुकूल पहल है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और सख्ती से निगरानी की जाए, तो यह विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षित रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है और प्रथम-बार श्रमिकों को सशक्त बना सकती है।

## डिजिटल रूप से प्रमाणित गोद लेना

**प्रसंग**

हाल ही में CARA ने स्पष्ट किया कि ईमेल के माध्यम से भेजे गए डिजिटल रूप से प्रमाणित गोद लेने के आदेश वर्तमान कानूनों के तहत वैध हैं, और अब भौतिक प्रतियों की आवश्यकता नहीं है।

**समाचार के बारे में**

• CARA ने कहा कि गोद लेने के आदेश की हार्ड कॉपी अब आवश्यक नहीं है।
• ईमेल के माध्यम से दत्तक माता-पिता को भेजी गई डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रतियां पूरी तरह कानूनी रूप से वैध हैं।
• यह स्पष्टता किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप है।

• यह कागजरहित शासन और तेज़ गोद लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है।

**केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)**

• CARA महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
→ इसे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 68 के तहत कानूनी दर्जा प्राप्त है।

• इसकी स्थापना 1990 में हुई, और यह देश में तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोद लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
→ यह भारत में मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से कार्य करता है।

• CARA भारत की केंद्रीय प्राधिकरण है जो अंतर-देशीय गोद लेने पर हेग कन्वेंशन (1993) के अंतर्गत कार्य करती है।
→ भारत ने इस संधि की पुष्टि 2003 में की, जिससे अंतरराष्ट्रीय कानूनी समर्थन प्राप्त हुआ।

• यह अनाथ, परित्यक्त, और समर्पित बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया संभालता है।

→ गोद लेने की प्रक्रिया **चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम (CARINGS)** के माध्यम से होती है।

• गोद लेने को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून हैं: किशोर न्याय अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, तथा संरक्षक और वार्ड अधिनियम।
→ यह धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की कानूनी आवश्यकताओं को शामिल करता है।

• सभी **बाल देखभाल संस्थानों (CCIs)** को JJ अधिनियम के तहत पंजीकृत और CARA से जुड़ा होना आवश्यक है।
→ यह निगरानी और जवाबदेही की एकरूपता को बढ़ावा देता है।

**चुनौतियाँ**

• डिजिटल दत्तक आदेशों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार किया जा सकता है।

→ उदाहरण: कुछ राज्य अधिकारी अभी भी प्रिंटेड आदेश की मांग करते हैं।

• कई ज़िलों में दत्तक प्रक्रिया अभी भी धीमी है।

→ उदाहरण: विशेषीकृत दत्तक एजेंसियों में सीमित स्टाफ अनुमोदन में देरी करता है।

• अंतरदेशीय गोद लेने की प्रक्रिया में कानूनी जटिलताएं माता-पिता को भ्रमित करती हैं।

→ उदाहरण: OCI/विदेशी जोड़ों को लंबी प्रक्रिया और अनेक सत्यापन से गुजरना पड़ता है।

• CARA दिशानिर्देशों के बारे में पर्याप्त जागरूकता अभियान नहीं हैं।

→ उदाहरण: कई इच्छुक माता-पिता CARINGS पोर्टल और प्रक्रियाओं से अनजान हैं।

**आगे का रास्ता**

• सभी राज्यों में डिजिटल आदेश को स्वीकार करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं।
→ उदाहरण: CWC और ज़िला अदालतों के लिए संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित करें।

• विशेषीकृत दत्तक एजेंसियों (SAA) और जिला बाल संरक्षण इकाइयों (DPU) को अधिक स्टाफिंग और प्रशिक्षण दें।
→ उदाहरण: दत्तक अधिकारियों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करें।

• NRI और OCI आवेदकों के लिए अंतरदेशीय गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाएं।

→ उदाहरण: क्षेत्रीय भाषाओं में चरणबद्ध ऑनलाइन मार्गदर्शन शुरू करें।

• मीडिया के माध्यम से CARINGS पोर्टल और JJ अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार करें।

→ उदाहरण: ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए टीवी और रेडियो विज्ञापन का उपयोग करें।

**निष्कर्ष**

CARA की डिजिटल मान्यता पारदर्शी, तेज़ और कागज़रहित दत्तक प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, जो आधुनिक प्रशासन के अनुरूप है। बेहतर जागरूकता और सरल प्रक्रियाओं के साथ भारत में गोद लेने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समावेशी और बाल-केंद्रित बन सकती है।

## अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना

**प्रसंग**

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना** को मंजूरी दी है, जिसमें ₹1 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

**समाचार के बारे में**

• RDI योजना का उद्देश्य अनुसंधान, विकास और नवाचार में निजी निवेश को बढ़ावा देना है।

• यह निजी क्षेत्र की अनुसंधान परियोजनाओं को दीर्घकालिक, कम या शून्य ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है।

• यह योजना आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए उदीयमान और रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित है।

• एक द्विस्तरीय निधि संरचना के माध्यम से इस योजना के तहत धन का प्रबंधन और वितरण किया जाएगा।

**वित्त पोषण तंत्र**

• यह योजना निजी नवाचार को समर्थन देने के लिए **दो-स्तरीय वित्त पोषण प्रणाली** अपनाएगी।
• **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (ANRF)** के तहत एक **विशेष प्रयोजन निधि (SPF)** बनाई जाएगी, जो मुख्य पूंजी को प्रबंधित करेगी।
• SPF से प्राप्त धनराशि द्वितीय स्तर के निधि प्रबंधकों को वितरित की जाएगी।

• ये प्रबंधक दीर्घकालिक सहायता **कम-ब्याज या ब्याज-मुक्त ऋण** के रूप में प्रदान करेंगे।
• **इक्विटी निवेश** का भी उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से स्टार्टअप्स और उभरते उपक्रमों के लिए।
• **डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स** या उच्च प्रौद्योगिकी नवाचार मंचों को वित्तीय समर्थन दिया जा सकता है।

**योजना की प्रमुख विशेषताएं**

• यह योजना निजी अनुसंधान परियोजनाओं में **वित्त पोषण की कमी** को दूर करने का प्रयास करती है।

→ विशेष रूप से डीप-टेक और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में।

• यह उच्च तकनीकी तत्परता स्तर (TRL) वाली परियोजनाओं को सहायता देगी।

→ जो व्यावसायीकरण के करीब हैं उन्हें प्राथमिकता मिलेगी।

• स्टार्टअप्स के लिए **डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स** की स्थापना की जाएगी।
→ रणनीतिक तकनीकों में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

• **ऋण या इक्विटी** के रूप में लचीले वित्तीय मॉडल को अपनाया जाएगा।
→ जिससे शुरुआती और विकासशील दोनों प्रकार की कंपनियों को मदद मिल सकेगी।

• योजना की रणनीतिक दिशा का निर्धारण **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (ANRF)** द्वारा किया जाएगा।
→ प्रधानमंत्री इस संस्था के अध्यक्ष होंगे, जिससे शीर्ष स्तर की निगरानी सुनिश्चित होगी।

• योजना के कार्यान्वयन का नोडल विभाग **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** होगा।

→ नीति निष्पादन और समन्वय की जिम्मेदारी निभाएगा।

**चुनौतियाँ**

• भारत में निजी क्षेत्र का अनुसंधान निवेश वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत कम है।

→ उदाहरण: भारतीय निजी कंपनियां GDP का 0.3% से भी कम R&D में लगाती हैं।

• जोखिम अधिक और लाभ मिलने में समय लगता है, जिससे निवेशक हतोत्साहित होते हैं।

→ उदाहरण: डीप-टेक परियोजनाओं को लाभदायक बनने में वर्षों लग जाते हैं।

• स्टार्टअप्स और लघु कंपनियों के पास पूंजी तक सीमित पहुंच है।
→ उदाहरण: पारंपरिक बैंक ऋण के लिए इनके पास पर्याप्त गिरवी नहीं होती।

• कई एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी कार्यान्वयन में देरी कर सकती है।

→ उदाहरण: ANRF, DST और निधि प्रबंधकों की भूमिकाओं में ओवरलैपिंग हो सकती है।

**आगे का रास्ता**

• स्टार्टअप्स को वित्तीय अवसरों की जानकारी देने के लिए **जागरूकता अभियान** चलाएं।

→ उदाहरण: राज्य स्तर पर कार्यशालाएं और वेबिनार आयोजित किए जाएं।

• द्वितीय-स्तरीय निधि प्रबंधकों का **पारदर्शी चयन** और समय पर फंड जारी किया जाए।

→ उदाहरण: परियोजनाओं के चयन के लिए स्वतंत्र समीक्षा समितियां गठित हों।

• **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी को बढ़ावा दें।

→ उदाहरण: निजी कंपनियों को IIT या CSIR लैब के साथ सहयोग के लिए प्रेरित करें।

• आयात पर निर्भरता कम करने हेतु स्थानीय तकनीकों का विकास करें।

→ उदाहरण: स्वदेशी सेमीकंडक्टर या बैटरी तकनीक को प्राथमिकता दें।

**निष्कर्ष**

RDI योजना भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने की दिशा में परिवर्तनकारी कदम है। यदि इसका सुचारु रूप से क्रियान्वयन किया गया, तो यह वित्तीय अंतर को पाट सकती है और उच्च-प्रभाव वाली तकनीकी परियोजनाओं में निजी भागीदारी को सशक्त बना सकती है।

## भारत में असमानता

**संदर्भ:**

विश्व बैंक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को मध्यम रूप से कम असमानता वाले देश के रूप में स्थान दिया गया है, जो गरीबी में कमी और समावेशी विकास में स्पष्ट प्रगति का संकेत है।

**परिचय:**

- विश्व बैंक की रिपोर्ट: वसंत 2025 गरीबी और इक्विटी संक्षिप्त विवरण (Spring 2025 Poverty and Equity Brief) का हिस्सा।
- गिनी इंडेक्स स्कोर: भारत का स्कोर 25.5 है (मध्यम रूप से कम असमानता)।
- वैश्विक रैंकिंग: इस इंडेक्स के अनुसार चौथा सबसे अधिक समान देश।
- वैश्विक तुलना: चीन, अमेरिका और ब्राजील से बेहतर स्कोर।

**रिपोर्ट के निष्कर्ष:**

- गरीबी में कमी: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी में गिरावट देखी गई।
- भारत का गिनी इंडेक्स 28.8 (2011) से सुधरकर 25.5 (2023) हो गया, जो अधिक समान आय वितरण को दर्शाता है।
- सरकारी योजनाएँ: पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे कार्यक्रमों ने गरीब परिवारों का समर्थन किया।
- वित्तीय समावेशन: जन धन योजना ने बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बढ़ाई।
- 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए (PMJDY)।
- सामाजिक सुरक्षा जाल: मुफ्त खाद्यान्न योजनाओं ने पोषण सुरक्षा में सुधार किया।
- स्वास्थ्य पहल: आयुष्मान भारत ने गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच का विस्तार किया।
- रोजगार सहायता: मनरेगा जैसी योजनाओं ने ग्रामीण रोजगार के अवसर प्रदान किए (₹5 लाख के स्वास्थ्य कवर के लिए 41 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए गए)।

**चुनौतियाँ:**

- डेटा सीमाएँ: उपभोग-आधारित गिनी आय-आधारित विषमताओं को छोड़ सकता है।
- शहरी-ग्रामीण विभाजन: बुनियादी ढाँचे और अवसरों में अभी भी बड़ा अंतर है।
- लैंगिक अंतर: कई क्षेत्रों में महिला कार्यबल भागीदारी कम बनी हुई है।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था: 90% से अधिक श्रमिक अभी भी अनौपचारिक रोजगार में हैं।

**आगे का रास्ता:**

- डेटा गुणवत्ता में सुधार: NSS और PLFS जैसे मिश्रित-तरीके वाले सर्वेक्षणों को अपनाना।
- आय के अंतर को कम करना: जीवन यापन के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूनों और कर सुधारों को लागू करना।
- समावेशन पर ध्यान केंद्रित करें: ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का विस्तार करें।
- औपचारिक नौकरियों को बढ़ावा दें: श्रम-प्रधान उद्योगों और डिजिटल सेवाओं को प्रोत्साहित करें।

**निष्कर्ष:**

भारत का सुधरा हुआ गिनी स्कोर गरीबी उन्मूलन में हुए लाभ को दर्शाता है, फिर भी छिपी हुई असमानताएँ बनी हुई हैं। वास्तविक समानता के लिए संतुलित नीतियां, गुणवत्तापूर्ण डेटा और समावेशी रोजगार वृद्धि आवश्यक हैं।

## भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक

**प्रसंग:**

भारत ने *Phenome India* परियोजना के तहत अपना पहला

**राष्ट्रीय बायोबैंक** लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य **भारतीय जनसंख्या डेटा** के माध्यम से **व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल** और **जीनोमिक अनुसंधान** को बढ़ावा देना है।

**परिचय:**

- **उद्घाटन:** नई दिल्ली स्थित **CSIR–IGIB** में केंद्रीय विज्ञान मंत्री द्वारा शुरू किया गया।
- **संबद्धता:** यह *Phenome India* नामक दीर्घकालिक स्वास्थ्य अध्ययन का हिस्सा है।
- **विकासकर्ता: CSIR–IGIB** द्वारा विकसित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित।
- **उद्देश्य:** यह जानना कि **जीन्स और जीवनशैली** भारतीयों में बीमारियों को कैसे प्रभावित करते हैं।

**राष्ट्रीय बायोबैंक की विशेषताएं:**

- **डेटा संग्रहण:** 10,000 से अधिक व्यक्तियों के **जीनोमिक, जीवनशैली और स्वास्थ्य डेटा** को संकलित करता है।
- **भारतीय संदर्भ के अनुसार अनुकूलित:** यह **जाति, क्षेत्रीय और आर्थिक विविधताओं** को ध्यान में रखता है।
- **प्रेरणा स्रोत:** यह **यूके बायोबैंक** से प्रेरित है, पर भारतीय ज़रूरतों के अनुसार विकसित किया गया है।
- **रोग केंद्रित: दुर्लभ बीमारियाँ, कैंसर, मधुमेह** आदि पर शोध को प्राथमिकता देता है।
- **एआई और सीआरआईएसपीआर तकनीक: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जीन-संपादन** आधारित निदान का समर्थन करता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव:** सरकारी अस्पतालों में **कम लागत वाली व्यक्तिगत चिकित्सा** का मार्ग प्रशस्त करता है।

**फेनोम इंडिया परियोजना**

- **Phenome India** परियोजना **CSIR** का पहला **राष्ट्रीय स्वास्थ्य अध्ययन** है जो **कार्डियो-मेटाबोलिक रोगों** की दीर्घकालिक निगरानी पर केंद्रित है। यह **7 दिसंबर, 2023** को शुरू हुआ था और **17 राज्यों व 24 शहरों** की विविध आबादी को शामिल करता है।
- लगभग **10,000 प्रतिभागी**, जिनमें **CSIR कर्मचारी, पेंशनधारक और उनके जीवनसाथी** शामिल हैं, इस परियोजना का हिस्सा हैं। यह **स्वास्थ्य, जीवनशैली, शारीरिक माप और आनुवंशिक प्रोफाइल** पर डेटा एकत्र करता है।
- अध्ययन में **नैदानिक, जैव रासायनिक, जीवनशैली और इमेजिंग डेटा** एकत्र किया जाता है ताकि भारतीयों में स्वास्थ्य प्रवृत्तियों को समझा जा सके। इससे **रोगों की प्रगति, जोखिम कारक** और **पर्यावरणीय प्रभावों** की पहचान में मदद मिलती है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य **भारत-विशिष्ट जोखिम मॉडल** विकसित करना है, खासकर **मधुमेह, हृदय और यकृत रोगों** के लिए। ये मॉडल **प्रारंभिक पहचान** और **लक्षित उपचार** को दिशा देंगे।
- यह परियोजना **पूर्वानुमानात्मक, निवारक, व्यक्तिगत और सहभागी (P4) स्वास्थ्य देखभाल** को बढ़ावा देती है, जो **भारतीय आनुवंशिक विविधता** पर आधारित है। यह **कम लागत वाली, जनसंख्या-विशिष्ट समाधान** प्रदान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूती देती है।

**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)**

- **CSIR**, भारत की सबसे बड़ी **अनुसंधान एवं विकास (R&D)** संस्था है, जिसकी स्थापना **1942** में हुई थी। यह **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के अंतर्गत **स्वायत्त निकाय** के रूप में कार्य करता है और **नई दिल्ली** में मुख्यालय स्थित है।
- यह संस्था **विमानन, जीवविज्ञान, रसायन, भूविज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान** सहित कई क्षेत्रों में **वैज्ञानिक अनुसंधान** करती है। **CSIR** का लक्ष्य **राष्ट्रीय नवाचार** को बढ़ावा देना और **औद्योगिक विकास** में योगदान देना है।
- भारत के **प्रधानमंत्री** इसके **अध्यक्ष (Ex-officio)** होते हैं और संचालन मंडल का नेतृत्व **महानिदेशक** करते हैं।
  **सलाहकार मंडल** में विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों के **विशेषज्ञ** होते हैं, जिनका कार्यकाल **तीन वर्ष** का होता है।

**चुनौतियाँ:**

- **डेटा गोपनीयता:** संवेदनशील जीनोमिक डेटा की **सुरक्षा और दुरुपयोग से बचाव** बेहद आवश्यक है।
- **भागीदारी की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों में **स्वास्थ्य साक्षरता** की कमी से **डेटा संग्रहण में बाधा** आती है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** कई प्रयोगशालाओं में **उन्नत भंडारण और अनुक्रमण उपकरणों** की **अनुपलब्धता** है।
- **नैतिक जटिलताएँ: आदिवासी और वंचित समुदायों** से सहमति प्राप्त करना अब भी एक **चुनौतीपूर्ण कार्य** है।

**आगे की राह:**

- **मजबूत डेटा कानून: जीनोमिक डेटा संरक्षण** के लिए सख्त और स्पष्ट **विधिक प्रावधान** लागू किए जाएं।
- **जागरूकता अभियान: आशा कार्यकर्ताओं** के माध्यम से ग्रामीणों को **परियोजना के महत्व** के बारे में शिक्षित किया जाए।
- **प्रयोगशाला सहयोग: टियर-2 शहरों** की लैब्स को **सैंपल संग्रह और परीक्षण** के लिए **वित्तीय सहायता** दी जाए।
- **सर्वसमावेशी भागीदारी: स्थानीय एनजीओ** की मदद से **विविध समुदायों** को शामिल किया जाए।

**निष्कर्ष:**

भारत का **राष्ट्रीय बायोबैंक**, चिकित्सा अनुसंधान का एक **ऐतिहासिक कदम** है, जो **व्यक्तिगत और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं** की दिशा में एक **महत्वपूर्ण परिवर्तन** ला सकता है। **सही नीतियों और सुरक्षा उपायों** के साथ यह **सार्वजनिक स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी** के क्षेत्र में **क्रांति ला सकता है**।

## एंटी-डंपिंग शुल्क

**प्रसंग:**

चीन ने यूरोपीय ब्रांडी, विशेष रूप से फ्रेंच कॉन्याक पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है, जो कि यूरोपीय संघ द्वारा चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी की जांच के जवाब में है। इससे व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है।

**परिचय:**

- **नए शुल्क:** चीन ने ईयू ब्रांडी पर **27.7% से 34.9% तक** शुल्क लगाया है।
- **अवधि:** ये उपाय **6 जुलाई, 2025** से शुरू होकर **पाँच वर्षों** तक लागू रहेंगे।
- **लक्ष्य उत्पाद:** मुख्य रूप से **फ्रेंच कॉन्याक**, जो यूरोपीय संघ के लक्जरी निर्यात का हिस्सा है।
- **कारण:** यूरोपीय संघ द्वारा **चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी** की जांच के जवाब में लगाया गया।

**विशेषताएँ / प्रावधान:**

- **व्यापार सुरक्षा उपकरण:** एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्देश्य **सस्ती और अनुचित कीमतों पर आयात को रोकना** है।
- **डब्ल्यूटीओ का अनुपालन:** यह **GATT 1994 के अनुच्छेद VI** और **एंटी-डंपिंग समझौते** के तहत अनुमत है।
- **चीन की कार्रवाई:** यह **ईयू ब्रांडी मूल्य निर्धारण की औपचारिक जांच** के बाद की गई है।
- **प्रतिकारात्मक संकेत:** इसे **यूरोपीय संघ के खिलाफ चीन की आर्थिक प्रतिक्रिया** के रूप में देखा जा रहा है।
- **व्यापक दायरा:** यह **चीन और पश्चिम के बीच व्यापक व्यापार संघर्ष** को दर्शाता है।
- **कानूनी आधार:** यह **स्थानीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचाने वाले अनुचित व्यापार व्यवहारों** पर आधारित है।

**एंटी-डंपिंग शुल्क (ADD):**

- एंटी-डंपिंग शुल्क एक **ऐसा टैरिफ है** जिसे कोई देश **अपने घरेलू उद्योग की रक्षा** के लिए लगाता है, जब किसी उत्पाद को **उसके वास्तविक बाजार मूल्य से कम** कीमत पर आयात किया जाता है।
- **डंपिंग तब होती है** जब कोई उत्पाद **विदेश में घरेलू मूल्य से कम कीमत पर बेचा जाता है।** **उदाहरण:** चीन में ₹35 प्रति वर्ग फुट में बिकने वाली टाइल्स भारत में ₹20 में बेची जा रही हैं।
- डंपिंग से **घरेलू उद्योगों को नुकसान** होता है क्योंकि वे सस्ती कीमतों का मुकाबला नहीं कर पाते। **उदाहरण:** इंडोनेशिया से सस्ती आयातित कागज के कारण भारतीय पेपर मिलों को घाटा हो रहा है।
- एंटी-डंपिंग शुल्क इन आयातों की कीमत बढ़ाकर डंपिंग के प्रभाव को **न्यून करने में मदद करता है**।
- भारत में एंटी-डंपिंग शुल्क **वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया जाता है**, जो **व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR)** की जांच और सिफारिशों के आधार पर होता है।
- **WTO** के तहत, सदस्य देश एंटी-डंपिंग समझौते का पालन करते हुए **न्यायोचित और अनुपातिक रूप से** शुल्क लगा सकते हैं।
- **ADD और प्रतिपूरक शुल्क (CVD)** में अंतर होता है — CVD उन आयातों पर लगाया जाता है जिन्हें **निर्यातक देश में सरकारी सब्सिडी मिली हो**। **उदाहरण:** चीन द्वारा सब्सिडी प्राप्त सोलर पैनलों पर प्रतिपूरक शुल्क।

**सनसेट समीक्षा:**

- यदि डंपिंग और घरेलू नुकसान की आशंका बनी रहती है तो एंटी-डंपिंग शुल्क को **5 वर्षों के लिए बढ़ाया** जा सकता है।
- यह **सबूतों या घरेलू उद्योग के अनुरोध** के आधार पर की गई समीक्षा के बाद तय किया जाता है।

- भारत **इस उपाय का सक्रिय रूप से प्रयोग करता है** — DGTR के माध्यम से **इस्पात, वस्त्र, रसायन** जैसे क्षेत्रों में।
- ये कार्रवाइयाँ **रोजगार सुरक्षा, बाजार स्थिरता और 'मेक इन इंडिया' जैसे अभियानों** को समर्थन देती हैं।

**चुनौतियाँ:**

- **व्यापार युद्ध का खतरा:** जैसा कि **अमेरिका-चीन के टैरिफ संघर्ष** में देखा गया, तनाव और बढ़ सकता है।
- **निर्यात में अनिश्चितता:** फ्रांस जैसे यूरोपीय निर्यातकों को **चीन में बिक्री में गिरावट** का सामना करना पड़ सकता है।
- **वैश्विक आपूर्ति पर प्रभाव:** ऐसे शुल्क **वैश्विक व्यापार प्रवाह और कीमतों** को बाधित कर सकते हैं।
- **WTO प्रणाली पर दबाव:** प्रतिशोधी शुल्क **बहुपक्षीय व्यापार विवाद समाधान प्रणाली** को कमजोर कर सकते हैं।

**आगे की राह:**

- **राजनयिक वार्ता:** ईयू और चीन को **WTO परामर्श मंचों** का उपयोग करके विवादों को सुलझाना चाहिए।
- **बाजार विविधीकरण:** प्रभावित ईयू निर्यातकों को **भारत, आसियान जैसे वैकल्पिक बाजार** तलाशने चाहिए।
- **स्पिलओवर की निगरानी:** भारत को इन विवादों को देखकर **अपनी व्यापार नीति को समायोजित** करना चाहिए।
- **DGTR को सशक्त करें:** भारत को **डंपिंग मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने** के लिए DGTR की क्षमता बढ़ानी चाहिए।

**निष्कर्ष:**

चीन के एंटी-डंपिंग शुल्क **वैश्विक व्यापार तनाव के बढ़ते चरण** को दर्शाते हैं। WTO के तहत यह **कानूनी है**, लेकिन यह **संवाद, नियम-आधारित व्यवस्था**, और **बाजार विविधता** की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

## भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR)

**प्रसंग:**

भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) वर्तमान में प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 93 है (2019–21 के आंकड़ों के अनुसार), जो मातृ स्वास्थ्य परिणामों में धीरे-धीरे हो रही प्रगति को दर्शाता है।

- **WHO की परिभाषा:** मातृ मृत्यु उस महिला की मृत्यु को कहा जाता है जो गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था समाप्त होने के 42 दिनों के भीतर हो, और यह मृत्यु गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं या ऐसी स्थितियों से हो जो गर्भावस्था के कारण और अधिक गंभीर हो गई हों।
- **मातृ मृत्यु अनुपात (MMR)** की गणना प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या के आधार पर की जाती है, जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के आंकड़ों पर आधारित होती है।

**नवीनतम आंकड़े (2019–21):**

- राष्ट्रीय MMR: 93
- केरल ने सबसे कम MMR (20) दर्ज किया, जबकि असम में सबसे अधिक (167) रहा।
- दक्षिणी राज्य प्रदर्शन में अग्रणी हैं, जबकि ईएजी (Empowered Action Group) राज्यों में मातृ स्वास्थ्य अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

**मातृ मृत्यु दर को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है**

- **स्वास्थ्य प्रणाली का संकेतक:** MMR स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, महिलाओं के अधिकारों और शासन की दक्षता का एक महत्वपूर्ण मानक है।
- **रोकथाम योग्य हानि:** अधिकांश मातृ मृत्यु समय पर देखभाल और सामान्य प्रसूति हस्तक्षेपों के माध्यम से रोकी जा सकती हैं।
- **वैश्विक लक्ष्य:** सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.1 के तहत, देशों का उद्देश्य 2030 तक MMR को 70 से नीचे लाना है। भारत को इस मानक तक पहुँचने के लिए अपनी प्रगति को तेज करना होगा।

**मातृ मृत्यु में योगदान देने वाली प्रमुख चुनौतियाँ**

**1. देखभाल में देरी – 'तीन प्रकार की देरी' मॉडल:**

- खतरे के संकेतों को पहचानने और देखभाल लेने का निर्णय लेने में देरी — जागरूकता की कमी या सामाजिक मानदंडों के कारण।
- स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने में देरी — विशेषकर आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में।
- अस्पतालों में उपयुक्त उपचार मिलने में देरी — विशेषज्ञों की कमी, सर्जरी की तैयारी या आवश्यक वस्तुओं जैसे रक्त की अनुपलब्धता के कारण।

**2. बुनियादी ढांचे की कमी:**

- 5,491 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) में से केवल 2,856 पहले रेफरल इकाई (FRU) के रूप में कार्यरत हैं।
- विशेषज्ञ डॉक्टरों के 66% से अधिक पद रिक्त हैं।

**3. चिकित्सा और स्वास्थ्य-संबंधी जोखिम:**

- प्रमुख चिकित्सीय कारण: प्रसवोत्तर रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप विकार, लंबे या अवरुद्ध प्रसव, संक्रमण, और असुरक्षित गर्भपात।
- एनीमिया, कुपोषण और तपेदिक या मूत्र मार्ग संक्रमण जैसे अंतर्निहित रोग — विशेषकर ईएजी राज्यों में — जोखिम को और बढ़ा देते हैं।

**सरकारी कार्यक्रम एवं हस्तक्षेप**

- **जननी सुरक्षा योजना (JSY):** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु माताओं और आशा कार्यकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK):** गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क परिवहन, जांच और प्रसव संबंधी सेवाएं प्रदान करता है।
- **FRU को सुदृढ़ करना:** सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिले में कम से कम 4 एफआरयू को कार्यशील बनाना है, जिनमें प्रशिक्षित कर्मचारी और रक्त भंडारण की सुविधा हो।
- **मातृ मृत्यु समीक्षा (MDR):** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, प्रत्येक मातृ मृत्यु की अनिवार्य समीक्षा की जाती है, ताकि सेवा वितरण में हुई चूक को समझा जा सके।
- **केरल मॉडल:** केरल की गोपनीय मातृ मृत्यु ऑडिट प्रणाली, स्टाफ प्रशिक्षण, और आपातकालीन तैयारी (जैसे यूटेरिन बलून टैम्पोनैड, एम्बोलिज्म किट) की मदद से भारत में सबसे कम MMR बनाए रखने में मदद मिली है।

**आगे की राह**

- **ईएजी राज्यों को प्राथमिकता:** विशेषज्ञों की नियुक्ति, ग्रामीण FRUs को उन्नत बनाने और समुदायों में जागरूकता बढ़ाने हेतु अधिक फंडिंग और प्रयास की आवश्यकता है।
- **आपातकालीन प्रसूति प्रतिक्रिया को मजबूत करना:** रक्त बैंक, सर्जरी सुविधाएं और एम्बुलेंस की 24×7 उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
- **फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को समर्थन:** ASHA और ANM के बीच समन्वय बढ़ाकर उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान और परामर्श को सुदृढ़ किया जा सकता है।
- **गर्भपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल सुधारना:** गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण, आयरन-फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, और नियमित जोखिम स्क्रीनिंग पर ध्यान देना आवश्यक है।
- **सफल मॉडलों को विस्तारित करना:** केरल की गोपनीय समीक्षा पद्धति को तमिलनाडु, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में अपनाया जा सकता है।

**निष्कर्ष:**

अधिकांश मातृ मृत्यु समय पर हस्तक्षेप और सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से रोकी जा सकती हैं। भारत को सेवाओं की पहुंच में अंतर को पाटना होगा, प्रसव के समय कुशल उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी, और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना होगा। सुरक्षित प्रसव ही नहीं, बल्कि **सुरक्षित मातृत्व** को भारत की मातृ स्वास्थ्य नीति का मुख्य उद्देश्य बनाना होगा।

## नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना

**प्रसंग:**

हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (NOS) के अंतर्गत चयनित 106 उम्मीदवारों में से 66 को अनंतिम पुरस्कार पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है, इसके पीछे धन की कमी और बजट स्वीकृति लंबित होने का हवाला दिया गया है।

**नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना (NOS) के बारे में:**

- यह केंद्र सरकार की एक योजना है, जो वंचित वर्ग के छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है।
- यह योजना शीर्ष QS रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालयों में मास्टर्स और पीएच.डी. कार्यक्रमों को कवर करती है।
- वित्तीय सहायता में ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, यात्रा व्यय, बीमा आदि शामिल हैं।
- यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित है, और अनुसूचित जातियों, विमुक्त जातियों तथा अन्य वंचित वर्गों को लक्षित करती है।

**योजना के प्रमुख प्रावधान:**

- **योग्यता:** स्नातक/परास्नातक डिग्री में न्यूनतम 60% अंक; आयु 35 वर्ष से कम।
- **आय सीमा:** पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
- **विश्वविद्यालय की शर्त:** QS की टॉप 500 रैंकिंग में आने वाले संस्थानों में प्रवेश आवश्यक।
- **वार्षिक सीमा:** प्रति वर्ष केवल 125 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
- **लैंगिक आरक्षण:** महिला उम्मीदवारों के लिए 30% आरक्षण।
- **चयन प्रक्रिया:** दो चरणों में चयन – QS रैंकिंग और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के आधार पर।

**चुनौतियाँ:**

- **वित्तीय विलंब:** इस वर्ष 66 चयनित छात्रों को धन की कमी के कारण पुरस्कार पत्र जारी नहीं हो सके।

→ *उदाहरण:* स्वीकृति मिलने के बावजूद पुरस्कार पत्र जारी होने में देरी।

- **सीमित छात्रवृत्तियाँ:** विदेश में पढ़ाई की बढ़ती आकांक्षाओं के बावजूद प्रति वर्ष केवल 125 छात्रवृत्तियाँ।
  → *उदाहरण:* हाल की चयन प्रक्रियाओं में 5000 से अधिक आवेदन।
- **प्रवेश निर्भरता:** केवल उन्हीं को पात्रता है जिन्होंने पहले से टॉप विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले लिया हो।
  → *उदाहरण:* फीस की समय-सीमा के कारण सभी के लिए संभव नहीं।
- **भौगोलिक सीमा:** प्रत्येक राज्य के लिए अधिकतम 10% सीटों की सीमा राज्यवार प्रतिनिधित्व को सीमित करती है।

  → *उदाहरण:* मेधावी छात्र राज्य कोटा के कारण चयन से वंचित हो जाते हैं।

**आगे का मार्ग:**

- **आवंटन में वृद्धि:** वार्षिक बजट और सीटों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि बढ़ती मांग पूरी हो सके।
  → *उदाहरण:* आकांक्षाओं के अनुरूप 200+ छात्रवृत्तियों का लक्ष्य रखा जाए।
- **समय पर धनराशि जारी हो:** शैक्षणिक सत्रों के अनुरूप वित्तीय स्वीकृति समय पर सुनिश्चित की जाए।
  → *उदाहरण:* प्रवेश चक्र से पहले अग्रिम बजटीय प्रावधान हो।
- **लचीले मापदंड:** QS टॉप 500 के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों को भी मान्यता दी जाए।
  → *उदाहरण:* क्षेत्रीय या विषय-विशिष्ट रैंकिंग को भी स्वीकार किया जाए।
- **निगरानी तंत्र:** चयन से लेकर निधि वितरण तक की प्रक्रिया पर नियमित निगरानी हो।
  → *उदाहरण:* नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर समर्पित डैशबोर्ड विकसित किया जाए।

**निष्कर्ष:**

नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना समाज के पिछड़े वर्गों को वैश्विक शिक्षा तक पहुंच दिलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन इसका प्रभावी लाभ तभी संभव है जब समय पर फंडिंग, अधिक समावेशी पात्रता और व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जाए, ताकि इन छात्रों को एक उज्जवल भविष्य की दिशा में सशक्त किया जा सके।

## डार्क वेब

**प्रसंग:**

केरल का एक 35 वर्षीय व्यक्ति हाल ही में डार्क वेब पर एक लेवल-4 विक्रेता के रूप में संचालन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि उसने एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म और क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन का उपयोग करते हुए मादक पदार्थों की बिक्री की।

**डार्क वेब क्या है?**

डार्क वेब इंटरनेट का एक छिपा हुआ हिस्सा है, जिसे सामान्य सर्च इंजन द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसमें पहुंचने के लिए विशेष ब्राउज़रों की आवश्यकता होती है, जैसे कि टोर (The Onion Router), जो उपयोगकर्ताओं को गुमनामी और एन्क्रिप्टेड संचार की सुविधा देता है।

**यह कैसे कार्य करता है?**

- **एक्सेस टूल:** किसी विशेष ब्राउज़र को इंस्टॉल करना आवश्यक होता है।
- **रूटिंग सिस्टम:** उपयोगकर्ता का डाटा कई यादृच्छिक नोड्स के माध्यम से भेजा जाता है, प्रत्येक स्तर पर डाटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है—इसीलिए इसे "ऑनियन रूटिंग" कहा जाता है।
- **वेब डोमेन:** डार्क वेब साइट्स ".onion" डोमेन का उपयोग करती हैं, जो सामान्य ब्राउज़रों और सर्च इंजन पर दिखाई नहीं देतीं।
- **विकेंद्रीकृत नेटवर्क:** इसका संचालन किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता, जिससे निगरानी और नियंत्रण अत्यंत कठिन हो जाता है।

**डार्क वेब की प्रमुख विशेषताएँ**

- **गोपनीयता और एन्क्रिप्शन:**

  उपयोगकर्ता की पहचान और ब्राउज़िंग गतिविधियां छिपी रहती हैं, जिससे विज़िटर और वेबसाइट ऑपरेटर दोनों की पहचान नहीं हो पाती।
- **डिजिटल मार्केटप्लेस:** इसमें कानूनी और अवैध दोनों प्रकार के बाजार, फोरम, डेटा रिपॉजिटरी और व्हिसलब्लोअर प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं।
- **सेंसरशिप-प्रतिरोधी पहुंच:** यह उन क्षेत्रों में सेंसरशिप से मुक्त जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है जहां सूचना पर प्रतिबंध होता है। पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सूचनादाता इसका सुरक्षित संचार के लिए उपयोग करते हैं।
- **साइबर अपराध का जोखिम:** डार्क वेब की गुमनामी इसे मादक पदार्थों, हथियारों, हैकिंग टूल्स और चुराए गए डेटा के अवैध व्यापार का अड्डा बना देती है। लेयर

आधारित एन्क्रिप्शन के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन्हें ट्रैक करना बेहद कठिन होता है।

**चुनौतियाँ**

- **कानून प्रवर्तन की सीमाएँ:** डार्क वेब की जांच के लिए उन्नत साइबर फॉरेंसिक और अंतरराष्ट्रीय समन्वय की आवश्यकता होती है, जो कई एजेंसियों के पास नहीं है।

  → *उदाहरण:* एडिसन के मामले में, परत-दर-परत एन्क्रिप्शन और गुमनामी के कारण पहचान में देरी हुई।

- **कानूनी अस्पष्टता:** वर्तमान कानून अक्सर डार्क वेब अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते और सीमा-पार अधिकार क्षेत्र को नहीं दर्शाते।

  → *उदाहरण:* कई मामलों में यह स्पष्ट नहीं होता कि मामला आईटी एक्ट के अंतर्गत आता है या एनडीपीएस एक्ट के तहत।

- **क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग:** वर्चुअल करेंसी से किए गए लेनदेन बैंकिंग प्रणाली से बाहर होते हैं, जिससे वित्तीय निगरानी कठिन हो जाती है।
  → *उदाहरण:* ड्रग्स और हथियारों की खरीद के लिए मोनेरो या बिटकॉइन का उपयोग किया जाता है, जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है।

- **जन जागरूकता की कमी:** उपयोगकर्ताओं की सीमित जानकारी, विशेष रूप से युवाओं को, डार्क वेब की धोखाधड़ीपूर्ण साइटों और खतरनाक नेटवर्कों का शिकार बना सकती है।

**आगे का मार्ग**

- **विशेषीकृत साइबर इकाइयाँ:** प्रशिक्षित कर्मियों और वैश्विक सहयोग के साथ समर्पित डार्क वेब निगरानी सेल स्थापित की जाएं।
  → *उदाहरण:* इंटरपोल की डार्कनेट टास्क फोर्स जैसी साझेदारियों से जांच क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है।

- **क्रिप्टोकरेंसी पर कड़ा नियंत्रण:** केवाईसी नियम लागू कर और ब्लॉकचेन विश्लेषण द्वारा अवैध लेनदेन की निगरानी की जाए।
  → *उदाहरण:* Chainalysis जैसी कंपनियाँ सरकारों को साइबर अपराध में क्रिप्टो ट्रेल्स ट्रैक करने में सहायता करती हैं।

- **कानूनी सुधार:** साइबर कानूनों को अद्यतन कर डार्क वेब गतिविधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए और दंड निर्धारित किया जाए।
  → *उदाहरण:* आईटी एक्ट और एनडीपीएस एक्ट में संशोधन कर प्रवर्तन की खामियों को दूर किया जा सकता है।

- **डिजिटल साक्षरता अभियान:** युवाओं और छात्रों को डार्क वेब के खतरों और कानूनी परिणामों के बारे में शिक्षित किया जाए।
  → *उदाहरण:* स्कूल और कॉलेज स्तर पर साइबर सुरक्षा जागरूकता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

**निष्कर्ष:**

डार्क वेब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। इसका प्रभावी मुकाबला समन्वित पुलिसिंग, अद्यतन कानूनों और जनजागरूकता के माध्यम से ही संभव है, जिससे एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

## भारत में क्षय रोग का बोझ

**संदर्भ:**

लगातार हो रहे हस्तक्षेपों के बावजूद, क्षय रोग (टीबी) भारत में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है, जो वैश्विक टीबी मामलों का 28% है। देश ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, लेकिन दवा-प्रतिरोधी स्ट्रेन का उभरना और स्वास्थ्य सेवा वितरण में कमियाँ इस प्रगति में बाधा बन रही हैं।

**समाचार के बारे में**

• टीबी का उच्च बोझ: धीरे-धीरे गिरावट के बावजूद, भारत में अभी भी टीबी के मामलों की एक बड़ी संख्या दर्ज की जाती है।

• दवा-प्रतिरोधी स्ट्रेन बढ़ रहे हैं: बहु-औषधि प्रतिरोधी (एमडीआर) और व्यापक रूप से दवा-प्रतिरोधी (एक्सडीआर) टीबी के मामले उपचार और नियंत्रण के प्रयासों को जटिल बनाते हैं।

• अपनाया गया नया उपचार: प्रतिरोधी टीबी के प्रभावी प्रबंधन के लिए बीपीएएल पद्धति शुरू की जा रही है।

भारत का उन्मूलन लक्ष्य: भारत का लक्ष्य 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पहले, 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है।

**क्षय रोग (टीबी) को समझना**

• क्षय रोग एक जीवाणुजनित रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन पेट, हड्डियों, लिम्फ नोड्स और यहाँ तक कि तंत्रिका तंत्र जैसे अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकता है।

• यह रोग हवा के माध्यम से फैलता है, मुख्यतः तब जब कोई व्यक्ति खांसते, छींकते या बोलते समय संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई बूंदों को साँस के माध्यम से अंदर ले लेता है।

**Different Forms of Tuberculosis**

| Type | Nature | Infectious? | Symptoms? |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pulmonary TB** | Occurs in the **lungs**; most common and **highly contagious** form. | Yes | Yes |
| **Latent TB** | Bacteria remain in the body in an **inactive state**; no symptoms appear. | No | No |
| **Active TB** | Bacteria multiply; immune system **fails to contain** the infection. | Yes | Yes |

**सरकारी पहल**

• बीपीएएल (क्षय-रोग नियंत्रण) व्यवस्था शुरू की गई: बेडाक्विलाइन, प्रीटोमैनिड और लाइनज़ोलिड को मिलाकर, उपचार की अवधि 24 महीने से घटाकर 6 महीने कर दी गई।

• केंद्रित अभियान शुरू किए गए: "टीबी हारेगा, देश जीतेगा" और निश्चय इकोसिस्टम जैसी पहल जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देती हैं।

• रोगियों के लिए पोषण सहायता: निक्षय पोषण योजना के तहत, रोगियों को उपचार के दौरान ₹500/माह मिलते हैं।

• निःशुल्क निदान और दवाएँ: राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) नैदानिक परीक्षणों और दवाओं तक निःशुल्क पहुँच सुनिश्चित करता है।

• सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया: टीबी चैंपियन, पूर्व रोगी और आशा कार्यकर्ता शीघ्र पहचान और देखभाल में सहायता करते हैं।

• वैश्विक समन्वय: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) विश्व टीबी दिवस (24 मार्च) मनाता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से वैश्विक प्रयासों पर नज़र रखता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

• अज्ञात सह-रुग्णताएँ: टीबी अक्सर मधुमेह, एनीमिया या शराब की लत के साथ होती है, जिससे मृत्यु दर का जोखिम बढ़ जाता है।

• स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी: ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में समय पर निदान के लिए उचित प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव है।

• कलंक और जागरूकता संबंधी समस्याएँ: कई मरीज़ सामाजिक कलंक या जानकारी के अभाव के कारण इलाज में देरी करते हैं।

• एमडीआर/एक्सडीआर उपचार की कठिनाइयाँ: दवा प्रतिरोध के कारण लंबे, महंगे और अधिक विषाक्त उपचार की आवश्यकता होती है, जिससे सफलता दर कम हो जाती है।

आगे की राह

• निदान प्रणालियों को मज़बूत करें: शीघ्र पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आणविक परीक्षणों (जैसे सीबी-एनएएटी) का विस्तार करें।

• संवेदनशील आबादी को लक्षित करें: आदिवासियों, शहरी मलिन बस्तियों और प्रवासी समूहों पर विशेष ध्यान देने से छूटे हुए मामलों में कमी आ सकती है।

• निजी क्षेत्र का सहयोग: मानकीकृत निदान और रिपोर्टिंग के लिए निजी चिकित्सकों को एनटीईपी से जोड़ें।

• रोगी-केंद्रित देखभाल को बढ़ावा दें: उपचार के पालन में सहायता के लिए निक्षय मित्र और टेली-परामर्श जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करें।

**निष्कर्ष**

टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई आगे बढ़ रही है, फिर भी निदान, प्रतिरोध प्रबंधन और जन जागरूकता में गंभीर कमियों को तत्काल दूर किया जाना चाहिए। चिकित्सा नवाचार, जमीनी स्तर पर भागीदारी और नीतिगत प्रतिबद्धता को मिलाकर एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी होगा।

## व्यापार: भारत, अमेरिका और रूस

**संदर्भ**

2025 के मध्य में, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित एक विधेयक का उद्देश्य रूस से तेल आयात करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाना है, जो भारत के ऊर्जा आयात और आर्थिक स्थिरता को गहराई से प्रभावित कर सकता है।

**समाचार के बारे में**

• अमेरिका द्वारा टैरिफ प्रस्ताव: रूसी कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 500% आयात शुल्क लगाकर उन्हें दंडित करने का लक्ष्य।

• भारत तेल आयात पर अत्यधिक निर्भर: भारत अपनी कुल कच्चे तेल की ज़रूरतों का 80% से अधिक आयात करता है।

• रूस-भारत तेल व्यापार में उछाल: भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 2022 में 2% से बढ़कर 2025 में 35% हो गई।

• भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: टैरिफ से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, आयात बिल बढ़ सकता है और चालू खाता घाटा बढ़ सकता है।

**वर्तमान रुझान**

• रूस से रणनीतिक आयात: रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से, रूस ने रियायती तेल की पेशकश की है, जिससे भारत का आयात बढ़ा है।

• वैश्विक तेल पदानुक्रम: अमेरिका, सऊदी अरब और रूस शीर्ष उत्पादक हैं; भारत तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

• कच्चे तेल के बाजार में अस्थिरता: प्रतिबंध और टैरिफ वैश्विक मूल्य अस्थिरता पैदा करते हैं, जिसका असर भारत जैसे विकासशील देशों पर पड़ता है।

• निर्भरता का जोखिम: विदेशी तेल पर भारत की अत्यधिक निर्भरता इसे बाहरी भू-राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

• मूल्य लाभ खतरे में: रूसी छूटों ने भारत को अरबों डॉलर बचाने में मदद की, लेकिन अमेरिकी टैरिफ उस लाभ को उलट सकते हैं।

• तेल भंडार की सीमाएँ: भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कीमतों में उछाल की स्थिति में केवल अस्थायी राहत प्रदान करते हैं।

**प्रमुख चुनौतियाँ**

• बढ़ती आयात लागत: टैरिफ भारत को महंगे बाजारों से खरीदारी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे व्यापार घाटा और बिगड़ सकता है।

• मुद्रास्फीति का दबाव: ईंधन की बढ़ती कीमतों से परिवहन और खाद्य लागत बढ़ सकती है, जिसका असर गरीबों पर पड़ेगा।

• विदेश नीति संतुलन: भारत को अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे राजनयिक तनाव का खतरा है।

• ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: विविधीकरण के बिना आयात पर अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

**आगे की राह**

• ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाना: भारत को खाड़ी देशों, अफ्रीका और अन्य गैर-प्रतिबंधित देशों के साथ सौदे तलाशने चाहिए।

• घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना: ओएनजीसी और तेल अन्वेषण को मजबूत करने से बाहरी कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो सकती है।

• नवीकरणीय क्षमता का विस्तार: सौर, पवन और जैव ईंधन में निवेश भविष्य में जीवाश्म ईंधन की मांग को कम करता है।

• तेल कूटनीति को मज़बूत करें: ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों का उपयोग करके स्थिर दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारियों पर बातचीत करें।

**निष्कर्ष**

भारत की आर्थिक क्षमता उसकी ऊर्जा सुरक्षा से गहराई से जुड़ी है। रूसी तेल पर प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ मुद्रास्फीति, आर्थिक तनाव और कूटनीतिक चुनौतियों को जन्म दे सकता है। भारत को अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाकर, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करके और रणनीतिक साझेदारियों को मज़बूत करके तेज़ी से कदम उठाने की ज़रूरत है।

## हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल

**प्रसंग**

भारत ने हाल ही में अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ETLD HCM का परीक्षण किया, जो घरेलू रक्षा तकनीक और रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता में एक बड़ी छलांग को दर्शाता है।

**समाचार के बारे में:**

- भारत ने DRDO द्वारा विकसित परियोजना "विष्णु" के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल ETLD HCM का परीक्षण किया।
- इस परीक्षण से भारत अमेरिका, चीन और रूस जैसे चुनिंदा हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में शामिल हो गया है।
- ETLD HCM स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करता है और मैक 8 (आवाज की गति से आठ गुना) की रफ्तार प्राप्त करता है, जिसकी रेंज 1,500 किमी तक है। PIB ने परीक्षण की पुष्टि की; इसे Indian Express और Economic Times ने भी रिपोर्ट किया।

**परीक्षण की प्रमुख विशेषताएँ:**

- **गति:** मैक 8 तक की गति प्राप्त करता है, जो अत्यंत तेज हमला सुनिश्चित करता है।
- **इंजन:** स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करता है, जो हवा से ऑक्सीजन लेकर ईंधन दक्षता बढ़ाता है।
- **रेंज:** 1,500 किमी तक की दूरी तय करने में सक्षम, रणनीतिक और सामरिक दोनों उद्देश्यों के लिए उपयुक्त।
- **पेलोड:** पारंपरिक या परमाणु हथियारों को 2,000 किलोग्राम तक ले जा सकता है।
- **लॉन्च प्लेटफॉर्म:** भूमि, वायु और समुद्र से प्रक्षेपण संभव, तैनाती में लचीलापन।

- **स्टेल्थ:** अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों (जैसे S-500) से भी पकड़ना कठिन।

**क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलों में अंतर**

| भेद के आधार पर | क्रूज़ मिसाइल | बैलिस्टिक मिसाइल |
|---|---|---|
| **1. उड़ान मार्ग** | कम ऊँचाई पर, ज़मीन से लगकर, पूर्व-निर्धारित मार्ग पर उड़ती है | ऊँचाई पर, पैरबोलिक पथ पर; वायुमंडल से बाहर जाकर वापस प्रवेश करती है |
| **उदाहरण** | ब्रह्मोस, टोमहॉक, निर्भय | अग्नि V, पृथ्वी-II, ट्राइडेंट II D5 |
| **2. मार्गदर्शन** | पूरे मार्ग में GPS, टेरेन मैपिंग आदि से नियंत्रित | केवल बूस्ट चरण में निर्देशित; मध्य व अंतिम चरण में बिना नियंत्रण |
| **उदाहरण** | JASSM, स्टॉर्म शैडो/SCALP | मिनिटमैन III, DF-26, इस्कंदर-M |
| **3. गति** | सबसोनिक या सुपरसोनिक (जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक है) | सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक (जैसे ICBM की गति 20,000 किमी/घं से अधिक) |
| **उदाहरण** | कालीब्र, AGM-86 ALCM | ह्वासोंग-15, अग्नि III |
| **4. रेंज** | मध्यम से लंबी दूरी: सामान्यतः 500–2,500 किमी | <1,000 किमी से >5,500 किमी तक (SRBM से ICBM तक) |
| **उदाहरण** | निर्भय (~1,000 किमी) | अग्नि V (>5,000 किमी), DF-5 (ICBM) |
| **5. पहचान** | कम ऊँचाई व छोटे रडार क्रॉस सेक्शन के कारण पहचान में कठिनाई | बूस्ट चरण में गर्मी और ऊँचाई के कारण आसानी से पहचाना जाता है |
| **उदाहरण** | ब्रह्मोस रडार से बच निकलता है | अग्नि II प्रक्षेपण के समय रडार पर स्पष्ट दिखता है |
| **6. सामरिक उपयोग** | सैन्य या रणनीतिक लक्ष्यों पर सटीक प्रहार के लिए प्रयुक्त | रणनीतिक, दीर्घ दूरी के परमाणु हमलों के लिए प्रयुक्त |
| **उदाहरण** | SCALP द्वारा सटीक हमले | ट्राइडेंट II द्वारा परमाणु प्रतिरोध प्रणाली |

**जेट इंजन के प्रकार**

| प्रकार | मुख्य विशेषताएँ |
|---|---|
| **टर्बोजेट** | प्रारंभिक जेट इंजन; वायु को टर्बाइन से संपीड़ित कर ईंधन जलाकर उच्च गति वाली गैसें उत्पन्न करता है। |
| **टर्बोप्रॉप** | गैस टर्बाइन प्रोपेलर को घुमाकर गति उत्पन्न करता है; धीमी और कम ऊँचाई पर उड़ने वाले विमानों में प्रयुक्त। |
| **टर्बोफैन** | आधुनिक वाणिज्यिक विमानों में उपयोग; टर्बोजेट और टर्बोप्रॉप का मिश्रण; कम ईंधन में अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करता है। |
| **रामजेट** | तेज गति से आगे बढ़ने पर वायु को स्वयं संपीड़ित करता है; कोई घूमने वाले भाग नहीं होते; सुपरसोनिक गति पर कार्य करता है। |
| **स्क्रैमजेट** | रामजेट का उन्नत संस्करण; हाइपरसोनिक गति पर कार्य करता है; वायु सुपरसोनिक गति से प्रवेश कर जलती है। |
| **पल्सजेट** | कोई चलायमान भाग नहीं; दहन की पुनरावृत्तियों से थ्रस्ट उत्पन्न करता है; कम दक्षता, प्रयोगात्मक प्रयोगों में प्रयुक्त। |

**चुनौतियाँ**

RACE IAS

- **उच्च लागत वाला अनुसंधान**: हाइपरसोनिक तकनीक के लिए अत्याधुनिक ढांचे की ज़रूरत, जैसे स्क्रैमजेट टेस्ट बेड्स।
- **तापीय दबाव**: 2,000°C तापमान सहन करना कठिन; विशेष कोटिंग और सामग्री की आवश्यकता।
- **मार्गदर्शन की जटिलता**: उच्च गति पर सटीक नेविगेशन की आवश्यकता; छोटी त्रुटि से बड़ा विचलन।
- **उत्पादन में देरी**: बड़े पैमाने पर उत्पादन में वर्षों लग सकते हैं; 2030 से पहले परिचालन संभव नहीं।

**आगे की राह**

- **अनुसंधान को मज़बूती**: स्वदेशी हाइपरसोनिक तकनीक के लिए DRDO को अधिक संसाधन और सुविधा दें।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग**: मित्र देशों जैसे फ्रांस और इज़राइल के साथ साझा अनुसंधान करें।
- **निजी क्षेत्र की भूमिका**: L&T जैसे भारतीय उद्योगों को निर्माण में शामिल करें।
- **परीक्षण एकीकरण**: जल, थल और वायु बलों के साथ संयुक्त परीक्षण संचालित करें।

**निष्कर्ष**

ETLD HCM भारत को वैश्विक हाइपरसोनिक शक्ति बनाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक क्षमता को मज़बूत करता है। निरंतर निवेश के साथ, यह भारत की रक्षा तकनीक को क्रांतिकारी रूप से बदल सकता है।

## भारत में असमानता

**प्रसंग**

हाल की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोग असमानता में कमी आई है, लेकिन अन्य अध्ययन आय और संपत्ति असमानता के बढ़ने को दर्शाते हैं, जिससे नीतिगत विरोधाभास उत्पन्न होता है।

**समाचार के बारे में**

- विश्व बैंक ने जिनी गुणांक में गिरावट दर्ज की — जो 2011–12 में 0.288 था, वह 2022–23 में घटकर 0.255 हो गया।
- यह संकेत करता है कि उपभोग के लिहाज़ से भारत वैश्विक स्तर पर सबसे कम असमानता वाले देशों में है।
- हालाँकि, **विश्व असमानता डेटाबेस (WID)** ने इससे असहमति जताई है और भारत में आय और संपत्ति की असमानता को कहीं अधिक बताया है।
- कई आंकड़ों की सीमाएं यह संदेह उत्पन्न करती हैं कि क्या आधिकारिक असमानता के अनुमान वास्तव में सटीक हैं।

**रिपोर्ट के अन्य निष्कर्ष**

- उपभोग असमानता घरेलू खर्च में अंतर को मापती है, न कि आय या संपत्ति को। यह कम दिखाई दे सकती है, लेकिन यह भ्रामक हो सकता है क्योंकि परिवार अक्सर आय घटने पर उधार लेकर या बचत से खर्च बनाए रखते हैं। इसलिए उपभोग आधारित डेटा अक्सर वास्तविक आर्थिक असमानता को कम करके दर्शाता है।
- **विश्व असमानता डेटाबेस (WID)** के अनुसार, भारत का **आय आधारित जिनी गुणांक 2023 में 0.61** है। इसका अर्थ है कि भारत में आय की असमानता अत्यधिक है, जहाँ एक छोटा वर्ग राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। इस मापदंड पर भारत से अधिक असमान केवल कुछ ही देश हैं।
- भारत का **संपत्ति आधारित जिनी गुणांक 0.75** और भी चिंताजनक है, जो दर्शाता है कि भूमि, संपत्ति और शेयर जैसे संसाधन भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास अत्यधिक मात्रा में केंद्रित हैं। यह संपत्ति स्वामित्व में गहरी संरचनात्मक असमानता को उजागर करता है।
- **घरेलू सर्वेक्षण**, जैसे हाउसहोल्ड कंजम्प्शन एक्सपेंडिचर सर्वे (HCES), अक्सर सबसे अमीर परिवारों को कवर नहीं कर पाते, क्योंकि वे उत्तर नहीं देते या अपनी आय को कम करके बताते हैं। इसके अलावा, भारत में आम तौर पर मिलने वाली **अनौपचारिक आय** को ऐसे सर्वेक्षणों में सटीक रूप से दर्ज करना मुश्किल होता है।
- **कर डेटा** की पहुंच भी सीमित है। **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** के अनुसार, देश की 140 करोड़ आबादी में केवल लगभग 6 करोड़ लोग ही आयकर दाखिल करते हैं। यह विशेषकर अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों के बड़े हिस्से को बाहर कर देता है।

**जिनी गुणांक**

- **परिभाषा:**
  जिनी गुणांक किसी आबादी के भीतर आय या संपत्ति की असमानता को मापता है।
- **सीमा:**
  यह 0 (पूर्ण समानता) से 1 (अधिकतम असमानता) तक होता है।
- **आधार:**
  यह **लॉरेन्ज वक्र** पर आधारित होता है, जो आय वितरण को दर्शाता है।
- **व्याख्या:**
  कम जिनी → अधिक समानता; उच्च जिनी →

अधिक असमानता।

- **उपयोग:**
  अर्थशास्त्र में असमानता का आकलन करने और नीति-निर्धारण हेतु उपयोग होता है।

**चुनौतियाँ**

- **अमीरों द्वारा कम रिपोर्टिंग डेटा को विकृत करती है।**
  *उदा.: अरबपति सर्वेक्षणों में वास्तविक संपत्ति नहीं दिखाते।*
- **HCES सर्वेक्षण ऊपरी आय वर्ग को छोड़ देता है।**
  *उदा.: अनौपचारिक क्षेत्र की आय प्रलेखित नहीं होती।*
- **संपत्ति स्तर पर कोई ट्रैकिंग नहीं।**
  *उदा.: संपत्ति और शेयर निवेश राष्ट्रीय आंकड़ों में पूरी तरह शामिल नहीं।*
- **जिनी गहराई नहीं दर्शाता।**
  *उदा.: शीर्ष 0.1% की हिस्सेदारी छिपी रहती है।*

**आगे की राह**

- **संपत्ति और उत्तराधिकार पर प्रगतिशील कर लगाना।**
  *उदा.: अल्ट्रा-रिच पर टैक्स लगाकर संपत्ति की एकाग्रता घटाएँ।*
- **स्वास्थ्य और शिक्षा में सार्वभौमिक सार्वजनिक सेवाएँ देना।**
  *उदा.: मुफ्त शिक्षा जीवन के अवसरों को बराबरी दे सकती है।*
- **कम-आय वर्गों में कौशल विकास को बढ़ावा देना।**
  *उदा.: MSMEs और ग्रीन सेक्टर के लिए प्रशिक्षण दें।*
- **कर और संपत्ति डेटा से पारदर्शिता सुधारना।**
  *उदा.: PAN, GST और सर्वेक्षण डेटा को लिंक करें।*

**निष्कर्ष**

एक न्यायसंगत और टिकाऊ अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए भारत को केवल उपभोग आधारित आंकड़ों से आगे बढ़कर **संरचनात्मक असमानता** से निपटना होगा। केवल **समावेशी विकास** और **पुनर्वितरण नीतियाँ** ही दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकती हैं।

## स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25

**प्रसंग:**

शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, अहमदाबाद को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 में सबसे स्वच्छ बड़े शहर के रूप में चुना गया। यह परिणाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक राष्ट्रीय सम्मान समारोह में घोषित किए गए, जो भारतीय शहरों की स्वच्छता के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

**स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है?**

यह एक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है जिसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें शहरों की रैंकिंग स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और नागरिक भागीदारी के आधार पर की जाती है।

- लक्ष्य: स्वच्छता को प्रतिस्पर्धात्मक और सहयोगात्मक मिशन बनाना।
- परिमाण: 4,500 से अधिक शहरों की भागीदारी और 14 करोड़+ नागरिकों की भागीदारी मोबाइल ऐप, फीडबैक और फील्ड विज़िट्स के माध्यम से।
- मुख्य क्षेत्र: घर-घर कचरा संग्रह, स्रोत पर अलगाव, सार्वजनिक शौचालयों की पहुंच, और शहरी सौंदर्यीकरण।

**2024–25 की मुख्य झलकियां: प्रमुख विजेता**

10 लाख+ जनसंख्या वाले शहर:

3. अहमदाबाद
4. भोपाल
5. लखनऊ

3–10 लाख जनसंख्या वाले शहर:

3. मीरा-भायंदर
4. बिलासपुर
5. जमशेदपुर

**अन्य श्रेणियाँ:**

- सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर: प्रयागराज
- सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड: सिकंदराबाद
- सफाई कर्मी सुरक्षा: विशाखापत्तनम, जबलपुर, गोरखपुर

**सुपर स्वच्छ लीग (SSL): एक नई श्रेणी**

यह श्रेणी उन शहरों को मान्यता देती है जो वर्षों से स्वच्छता में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।

- लक्ष्य: केवल एक बार की उपलब्धियों से आगे बढ़ते हुए, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रोत्साहन देना।
- पात्रता:
  - कम से कम 3-स्टार 'गर्बेज फ्री सिटी' रेटिंग
  - स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार उच्च रैंकिंग
  - नागरिक भागीदारी, ODF++ स्थिति, और स्रोत पर कचरा अलगाव में मजबूत प्रदर्शन
- उदाहरण: इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, मैसूरु, चंडीगढ़

**इस वर्ष के प्रमुख रुझान**

- मध्यम आकार के शहरों का उदय: बिलासपुर और जमशेदपुर जैसे शहर अब मेट्रो शहरों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
- 3R सिद्धांत का प्रसार: 'Reduce, Reuse, Recycle' को अपनाया गया।
- वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन: 12 शहरों को 7-स्टार और 22 को 5-स्टार रेटिंग मिली।
- छोटे शहरों को बराबरी का मौका: 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए स्कोरिंग प्रणाली को संशोधित किया गया।
- नागरिक भागीदारी: अब तक की सबसे अधिक—14 करोड़ लोगों की भागीदारी।

**नवाचार और अभियान**

- वेस्ट-टू-वेल्थ: रिसाइकल कचरे से बने उपहार सम्मानित व्यक्तियों को दिए गए।
- "Each One Clean One": टॉप 78 शहर कमजोर शहरों को मेंटर करेंगे।
- डंपसाइट सफाई अभियान: 15 अगस्त 2025 से 1-वर्षीय अभियान शुरू होगा।
- कुंभ प्रबंधन: प्रयागराज ने 66 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए कुंभ में उत्कृष्ट स्वच्छता प्रबंधन दिखाया।
- सफाईमित्र सुरक्षा: गोरखपुर और जबलपुर जैसे शहरों ने सफाईकर्मियों के अधिकार और सुरक्षा के लिए सराहना पाई।

**यह सर्वेक्षण क्यों महत्वपूर्ण है?**

- व्यवहार परिवर्तन: स्वच्छता अब केवल एक नियम नहीं, आदत बन रही है।
- रोजगार और स्टार्टअप: कचरा प्रबंधन से नए स्टार्टअप, महिला स्वयं सहायता समूह और हरित नौकरियाँ उत्पन्न हो रही हैं।
- प्रदर्शन मापन: शहर अपनी प्रगति को माप सकते हैं और एक-दूसरे से सीख सकते हैं।
- विकसित भारत 2047 लक्ष्य: स्वच्छ शहर इस लक्ष्य की नींव हैं।
- महिला नेतृत्व: स्कूल अभियानों और शून्य-कचरा प्रयासों में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं।

**निष्कर्ष**

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 केवल रैंकिंग नहीं है, यह भारत के शहरी स्वच्छता दृष्टिकोण में आ रहे परिवर्तन को दर्शाता है। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, नागरिक नेतृत्व और नीति-आधारित दृष्टिकोण भारत को एक स्वच्छ, टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा रहा है।

## रशियन सेंक्शंस एक्ट, 2025

**प्रसंग:**

भारत ने अमेरिका के एक नए विधायी प्रस्ताव — Russian Sanctions Act, 2025 — का कड़ा विरोध किया है। यह प्रस्ताव उन देशों पर भारी शुल्क लगाने की बात करता है जो रूसी तेल का आयात करते हैं, जैसे कि भारत। इस विधेयक को रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच गैर-पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

**क्या है Russian Sanctions Act, 2025?**

यह अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तुत एक विधेयक है, जिसे सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा पेश किया गया और जिसे द्विदलीय समर्थन प्राप्त है।

- मुख्य उद्देश्य: रूसी ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले देशों को लक्षित करके रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करना।
- प्रभाव क्षेत्र: रूसी मूल के तेल, गैस, कोयला, यूरेनियम और पेट्रोकेमिकल्स।
- अनुच्छेद 17: ऐसे देशों से आयात पर 500% तक का शुल्क लगाने का प्रस्ताव।
- द्वितीयक प्रतिबंध: भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिबंध की संभावना।
- राष्ट्रपति छूट: अमेरिकी राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में 6 महीने तक लागू करने में देरी कर सकते हैं।
- त्वरित कार्यान्वयन: विधेयक लागू होने के 50 दिनों के भीतर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश।

**भारत की चिंताएँ क्यों हैं?**

- ऊर्जा निर्भरता: भारत वर्तमान में लगभग 38% कच्चा तेल रूस से आयात करता है। प्रतिबंध से आपूर्ति बाधित हो सकती है और मूल्य अस्थिरता आ सकती है।
- रणनीतिक स्वायत्तता: भारत इसे विदेश नीति पर पश्चिमी दबाव के रूप में देखता है।
- सरकारी प्रतिक्रिया: भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने पश्चिमी देशों की दोगली नीति की आलोचना की है जो स्वयं रूस से व्यापार जारी रखते हैं।
- ऊर्जा विविधता रणनीति: भारत 40+ देशों से तेल आयात करता है और ऊर्जा निर्णय राष्ट्रीय हित के अनुसार लेता है।
- आर्थिक प्रभाव: आयात लागत में वृद्धि, महंगाई, और दीर्घकालिक समझौतों में बाधा संभव।

**व्यापक प्रभाव**

- भूराजनीतिक तनाव: यह भारत–अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से QUAD, व्यापार और रक्षा मामलों में।
- आर्थिक संप्रभुता: यह सवाल उठाता है कि कैसे प्रतिबंधों का उपयोग संप्रभु निर्णयों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
- ऊर्जा मार्ग बदलाव: भारत को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख करना पड़ सकता है।

**निष्कर्ष**

Russian Sanctions Act, 2025 वैश्विक राजनीति में बढ़ते तनाव को उजागर करता है, जहां संप्रभुता बनाम प्रतिबंध की लड़ाई चल रही है। भारत को अपने आर्थिक हित और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाना होगा। यह विधेयक भले ही लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता हो, लेकिन इसका क्रियान्वयन वैश्विक व्यापार को विभाजित कर सकता है और उन देशों को दंडित कर सकता है जो तटस्थ ऊर्जा नीति अपना रहे हैं।

## भारत में दहेज मृत्यु

**संदर्भ:**

उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और चंडीगढ़ जैसे राज्यों में दहेज से संबंधित मौतों में चिंताजनक वृद्धि ने इस गहरी सामाजिक बुराई और समय पर न्याय प्रदान करने में कानूनी तंत्र की विफलता की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया है।

**भारत में दहेज मृत्यु के बारे में**

**दहेज हत्याएँ क्या हैं?**

दहेज हत्याएँ तब होती हैं जब दहेज की माँग को लेकर लगातार उत्पीड़न या हिंसा के कारण किसी महिला की हत्या कर दी जाती है या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। ये भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304बी और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत दंडनीय हैं।

**प्रमुख आंकड़े और रुझान (2017–2022)**

- प्रतिवर्ष लगभग 7,000 मौतें दर्ज की जाती हैं (एनसीआरबी)।
- 6,100 से अधिक हत्याएं सीधे दहेज से संबंधित कारणों से जुड़ी हुई हैं।
- प्रत्येक वर्ष केवल 4,500 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया गया; 2022 में 3,000 से अधिक मामले जांच के अधीन रहे।
- दोषसिद्धि दर: प्रतिवर्ष लगभग 6,500 मुकदमों में से मात्र 100 में दोषसिद्धि।
- उच्च-घटना वाले राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा (लगभग 80% मामले)।
- शहरी चिंता: प्रमुख शहरों में दहेज हत्याओं में दिल्ली का योगदान 30% है।

**आगे बढ़ने का रास्ता**

- कानूनी सुदृढ़ीकरण: दहेज संबंधी मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें तथा एक वर्ष के भीतर मुकदमे का अनिवार्य रूप से पूरा होना।
- गवाह संरक्षण: पीड़ितों के परिवारों और मुखबिरों को सामाजिक और कानूनी धमकी से बचाना।
- पुलिस जवाबदेही: जांच और आरोप पत्र दाखिल करने में देरी या निष्क्रियता के लिए दंडित करें।
- सामुदायिक हस्तक्षेप: प्रतिगामी दृष्टिकोण को बदलने के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान, जिसमें पंचायतों, गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जाता है।
- आर्थिक सशक्तिकरण: लक्षित रोजगार योजनाओं और कानूनी साक्षरता अभियानों के माध्यम से महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना।

**निष्कर्ष**

दशकों से चले आ रहे क़ानूनों के बावजूद, दहेज हत्याएँ भारत में व्याप्त लैंगिक पूर्वाग्रहों और व्यवस्थागत उदासीनता का एक भयावह प्रतिबिंब बनी हुई हैं। इस हिंसा को समाप्त करने और महिलाओं के सम्मान और जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी प्रतिक्रिया - कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक - अत्यंत आवश्यक है।

## ब्लैक होल विलय GW231123

**प्रसंग:**

वैज्ञानिकों ने LIGO-Virgo-KAGRA (LVK) सहयोग के माध्यम से GW231123 का पता लगाया है, जो अब तक का सबसे विशाल ब्लैक होल विलय है। इसमें सूर्य के द्रव्यमान से 100 गुना और 140 गुना बड़े ब्लैक होल शामिल थे—जो तारकीय विकास और ब्लैक होल निर्माण के वर्तमान सिद्धांतों को चुनौती देते हैं।

**ब्लैक होल मर्जर GW231123 के बारे में:**

**ब्लैक होल विलय क्या है?**

यह एक उच्च-ऊर्जा खगोलीय घटना है जिसमें गुरुत्वाकर्षण तरंग उत्सर्जन के कारण दो ब्लैक होल अंदर की ओर सर्पिल गति करते हैं और अंततः विलीन होकर एक एकल, अधिक विशाल ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। ये घटनाएँ स्पेसटाइम को विकृत करती हैं

और गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं के माध्यम से इनका पता लगाया जा सकता है।

**मुख्य कार्यक्रम विवरण:**

- घटना का नाम: GW231123 (23 नवंबर, 2023 को LIGO के चौथे अवलोकन रन के दौरान पता चला)
- सम्मिलित द्रव्यमान: ~140 और ~100 सौर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल ~225 सौर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में विलीन हो गए
- द्रव्यमान अंतराल उल्लंघन: ब्लैक होल "निषिद्ध" 60-130 सौर द्रव्यमान सीमा में आते हैं - जो तारकीय मृत्यु के वर्तमान मॉडल का खंडन करता है
- स्पिन विशेषता: एक ब्लैक होल का स्पिन सापेक्षिकीय अधिकतम के करीब था - दुर्लभ और मॉडल करना कठिन
- उत्पत्ति दूरी: अनुमानित ~12 अरब प्रकाश वर्ष दूर
- डिटेक्शन नेटवर्क: LIGO (अमेरिका), विर्गो (इटली) और KAGRA (जापान) द्वारा प्रेक्षित

**आगे बढ़ने का रास्ता:**

- **खगोलभौतिकीय संशोधन:** तारकीय पतन और ब्लैक होल द्रव्यमान सीमा के सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन
- **विस्तारित अवलोकन:** चरम ब्रह्मांडीय घटनाओं को मान्य करने और मॉडल करने के लिए अधिक लगातार, बहु-डिटेक्टर अवलोकन रन
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान में वैश्विक प्रयासों को मजबूत करना (जैसे, आइंस्टीन टेलीस्कोप, कॉस्मिक एक्सप्लोरर)
- **डेटा मॉडलिंग उपकरण:** दूरस्थ अंतरिक्ष घटनाओं से उच्च-स्पिन, उच्च-द्रव्यमान तरंगों को डिकोड करने के लिए उन्नत AI मॉडल विकसित करें

**निष्कर्ष:**

GW231123 खगोल भौतिकी में एक मील का पत्थर है—यह न केवल स्थापित "द्रव्यमान अंतराल" की अवधारणा को तोड़ता है, बल्कि विचित्र या दूसरी पीढ़ी के ब्लैक होल की ओर भी इशारा करता है। यह ब्रह्मांड के अनदेखे कोनों को उजागर करने और ब्रह्मांडीय विकास की हमारी समझ का विस्तार करने में गुरुत्वाकर्षण तरंग विज्ञान के महत्व को पुष्ट करता है।

## बोलीविया- भारत

**प्रसंग** :

भारत ने बोलीविया में बीमारी के प्रकोप से निपटने में मदद के लिए वहां खसरा-रूबेला वैक्सीन की 3 लाख खुराकें भेजी हैं, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण साझेदारों के साथ, के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है।

**बोलीविया के बारे में:**

- **स्थान** : पश्चिम-मध्य दक्षिण अमेरिका में एक स्थलरुद्ध देश।
- **राजधानियाँ** : सुक्रे (संवैधानिक) और ला पाज़ (प्रशासनिक)।
- **पड़ोसी देश** : ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू की सीमाएँ।

**भौतिक विशेषताएं:**

- **एंडीज़ पर्वत** : दो पर्वतमालाओं - कॉर्डिलेरा ऑक्सिडेंटल और कॉर्डिलेरा ओरिएंटल - से आच्छादित। माउंट साजामा (6,542 मीटर) इसकी सबसे ऊँची चोटी है।
- **अल्टीप्लानो पठार** : एक उच्च ऊंचाई वाला मैदान (~12,000 फीट) जिसमें **टिटिकाका झील** (दुनिया की सबसे बड़ी नौगम्य झील) और अब सूख चुकी **पूपो झील शामिल है** ।
- **उयूनी साल्ट फ्लैट** : विश्व का सबसे बड़ा साल्ट फ्लैट (~10,400 वर्ग किमी), जो लिथियम निष्कर्षण के लिए महत्वपूर्ण है।
- **युंगास क्षेत्र** : एंडीज और निचले इलाकों को जोड़ने वाली वर्षावनीय ढलानें।
- **अमेज़न बेसिन** : बेनी, ममोरे और इटेनेज़ जैसी नदियाँ अमेज़न में बहती हैं।
- **चाको और ओरिएंट** : दक्षिणी गर्म मैदान और पूर्वी उष्णकटिबंधीय वर्षावन इन क्षेत्रों पर हावी हैं।

**भारत-बोलीविया द्विपक्षीय संबंध:**

- **स्वास्थ्य कूटनीति** : बोलीविया को भारत द्वारा दिया गया टीका दान दक्षिण-दक्षिण सहयोग, विशेष रूप से विकास साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत, में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
- **आपातकालीन सहायता** : इस खेप में न केवल टीके शामिल हैं, बल्कि बोलीविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया में सहायता के लिए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति भी शामिल है।
- **बहुपक्षीय समन्वय** : दोनों देश **जी-77** , **एनएएम** और **ब्रिक्स आउटरीच जैसे मंचों के माध्यम से सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं** ।
- **रणनीतिक क्षेत्र** : बोलीविया **लिथियम से समृद्ध है** — जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत खनन, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्रों में साझेदारी चाहता है।

**आगे बढ़ने का रास्ता:**

भारत को स्वास्थ्य संकट के दौरान लैटिन अमेरिकी देशों की सहायता के लिए अपनी दवा क्षमता का लाभ उठाना जारी रखना चाहिए। बदले में, उसे लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में संसाधन साझेदारी को गहरा करना चाहिए, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी सहयोग का निर्माण हो सके।

**निष्कर्ष:**

जन स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान बोलीविया को भारत द्वारा समय पर दी गई सहायता, दक्षिण-दक्षिण एकजुटता में उसके नेतृत्व को दर्शाती है। जैसे-जैसे वैश्विक चुनौतियाँ आपस में जुड़ती जा रही हैं, महाद्वीपों में समान विकास, लचीलापन और पारस्परिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए ऐसी साझेदारियाँ आवश्यक होंगी।

## संयुक्त राष्ट्र एसडीजी रिपोर्ट 2025

**प्रसंग** :

उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच पर प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रिपोर्ट 2025 इस बात पर प्रकाश डालती है कि **मापनीय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के 35% लक्ष्य या तो स्थिर हैं या पीछे जा रहे हैं** , जबकि 2030 की समय-सीमा तक केवल पाँच वर्ष शेष हैं। रिपोर्ट विकास में वैश्विक पिछड़ेपन को रोकने के लिए दिशा-निर्देशों में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है।

**संयुक्त राष्ट्र एसडीजी रिपोर्ट 2025 की मुख्य विशेषताएं**

**एसडीजी 2: शून्य भूख**

- **वैश्विक जनसंख्या का 9.1%** (लगभग 713-757 मिलियन) भूख का सामना करेगा।
- **2.33 अरब लोगों ने** मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया।
- गंभीर क्षेत्रीय असमानताएं: **उप-सहारा अफ्रीका में 23.2%** , तथा **दक्षिणी एशिया में 281 मिलियन लोग भूखे हैं** ।

**एसडीजी 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा**

- **57% संकेतक स्थिर या पीछे जा रहे हैं** ।
- सार्वभौमिक स्कूल पूर्णता, बुनियादी साक्षरता और लैंगिक समानता प्राप्त करने में व्यापक विफलता।

**एसडीजी 6: स्वच्छ जल एवं स्वच्छता**

- **2.2 अरब लोगों को** सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है।
- **3.4 अरब लोगों के** पास स्वच्छता संबंधी सुविधाएं नहीं हैं; **1.7 अरब लोगों के** पास हाथ धोने की सुविधा नहीं है।

**एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास**

- ट्रैक किये गये संकेतकों में से आधे में **कोई सुधार या गिरावट नहीं दिख रही है** ।
- **57.8% श्रमिक** अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं।
- **युवा बेरोजगारी दर 12.9%** है , जो **वयस्क दर (3.7%) से तीन गुना अधिक है** ।

**एसडीजी 10: असमानताओं में कमी**

- **आय, स्वास्थ्य, डिजिटल पहुंच** और **जलवायु लचीलेपन** में असमानता बढ़ रही है ।
- कोविड के बाद पुनर्वितरण तंत्र का कोई पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ।

**एसडीजी 14: जल के नीचे जीवन**

- **समुद्री-संबंधी 40% लक्ष्य पीछे जा रहे हैं** ।
- महासागरीय अम्लीकरण, अत्यधिक मछली पकड़ना और प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है।
- 2025 के संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में उल्लेख किया गया है कि एसडीजी 14 **सबसे कम वित्त पोषित है ।**

**एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण**

- **मातृ मृत्यु दर** और **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज** लक्ष्य पटरी से उतर गए हैं।
- महामारी के बाद का तनाव और कम निवेश स्वास्थ्य प्रणालियों को कमजोर कर रहा है।

**एसडीजी 12, 15, 16 (जिम्मेदार उपभोग, भूमि पर जीवन, शांति और न्याय)**

- 40-42% लक्ष्य प्रगति पर नहीं हैं।
- **वन संरक्षण** , **जैव विविधता संरक्षण** और **संस्थागत शासन** में उल्लेखनीय असफलताएँ ।

**नकारात्मक रुझानों की पहचान**

- **जलवायु संकट** : 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। **विश्व मौसम संगठन (WMO) ने चेतावनी दी है** कि तापमान में लगातार वृद्धि जारी रहेगी, जिससे भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुरक्षा को ख़तरा होगा।
- **अत्यधिक गरीबी** : **80 करोड़ से ज़्यादा लोग** अभी भी अत्यधिक गरीब हैं। मौजूदा गति से, **2030 तक 8.9% लोग अभी भी गरीबी में रह सकते हैं** , जो सतत विकास लक्ष्य 1 के लक्ष्यों से बहुत दूर है।
- **ऋण एवं सहायता में कटौती** : आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) **2024 में 7.1% तक गिर गई** , जिससे विशेष रूप से कम आय वाले देश प्रभावित होंगे।
- **सतत विकास लक्ष्य वित्तपोषण अंतराल** : **4 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष का अंतराल** बना हुआ है, जिससे महंगे

उधार के कारण कई विकासशील देशों में प्रगति अवरुद्ध हो रही है।

**सकारात्मक विकास**

- **एचआईवी प्रगति : 2010 से** वैश्विक एचआईवी संक्रमण में 40% की गिरावट आई है , जो एसडीजी 3 के अंतर्गत सफलता दर्शाती है।
- **मलेरिया नियंत्रण** : 2000 से अब तक **2.2 बिलियन मलेरिया के मामलों को रोका गया** तथा **12.7 मिलियन लोगों की जान बचाई गई ।**
- **सामाजिक सुरक्षा** : **वैश्विक जनसंख्या के 50% से अधिक लोगों को** अब सामाजिक सुरक्षा जाल तक पहुंच प्राप्त है, जिससे समावेशी विकास में सहायता मिल रही है।

**आगे का रास्ता: 2030 तक का रोडमैप**

- **वैश्विक वित्त में सुधार** : बहुपक्षीय वित्तपोषण का विस्तार करने और विकासशील देशों के लिए ऋण बोझ को कम करने के लिए **सेविला प्रतिबद्धता को लागू करना।**
- **छह महत्वपूर्ण त्वरक** :
    1. लचीली खाद्य प्रणालियाँ
    2. सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच
    3. समावेशी डिजिटल परिवर्तन
    4. गुणवत्ता की शिक्षा
    5. सभ्य रोजगार
    6. जलवायु और जैव विविधता संरक्षण
- **डेटा-संचालित शासन :** डेटा उपलब्धता और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में सुधार के लिए **मेडेलिन फ्रेमवर्क फॉर एक्शन** को लागू करना ।
- **लक्ष्य प्राथमिकता वाले सतत विकास लक्ष्य : सतत विकास लक्ष्य 2, 4, 6, 8 और 10** में तत्काल निवेश की आवश्यकता है , जिनका प्रदर्शन सबसे खराब है।
- **बहुपक्षीय सहयोग** : **जी-20, ब्रिक्स और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के माध्यम से सहयोग को मजबूत करना** , तथा राष्ट्रों को सामूहिक वैश्विक हित के प्रति पुनः प्रतिबद्ध करना।

**निष्कर्ष**

संयुक्त **राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025** एक स्पष्ट चेतावनी देती है: दुनिया अपनी 2030 की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में खतरनाक रूप से पीछे छूट गई है। हालाँकि स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में सुधार हुआ है, लेकिन व्यापक प्रतिगमन एक **प्रणालीगत परिवर्तन की माँग करता है** । आगे का रास्ता **वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में सुधार** , **प्रमुख त्वरक कारकों पर ध्यान केंद्रित करने** और **आँकड़ों पर आधारित एवं समतापूर्ण शासन सुनिश्चित करने में निहित** है। अब कार्रवाई करने का समय है, क्योंकि कार्रवाई में तेज़ी लाने में विफलता दशकों के विकास लाभों को कमज़ोर कर सकती है और वैश्विक असमानताओं को और बदतर बना सकती है।

## डीफाल्सीवैक्स: भारत का मलेरिया कवच

**प्रसंग**

भारत ने मलेरिया नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए , **एडफाल्सीवैक्स नामक** देश का **पहला स्वदेशी रूप से विकसित दो-चरणीय मलेरिया टीका विकसित किया है** , जिसे *प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह* **2030 तक** भारत के मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य के अनुरूप है।

**टीके के बारे में**

- **यह क्या है?**

  एडफाल्सीवैक्स एक **पुनः संयोजक टीका है** जो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के **दो चरणों को लक्षित करता है।**
- **इसे किसने विकसित किया? ICMR ने RMRC-भुवनेश्वर** , **NIMR** और **DBT-NII** के सहयोग से इसे बनाया है ।
- **इसका उत्पादन लैक्टोकोकस लैक्टिस** नामक एक **सुरक्षित, खाद्य-ग्रेड जीवाणु** से किया जाता है , जिसका उपयोग आमतौर पर डेयरी उत्पादों में किया जाता है।
- **मुख्य लक्ष्य:**

  मलेरिया संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना तथा समुदायों के भीतर परजीवी के **संचरण को रोकना ।**

**टीके की प्रमुख विशेषताएँ**

- **दोहरे चरण की सुरक्षा:** यह टीका **यकृत चरण** और **मच्छर संचरण चरण दोनों को लक्षित करता है** , जिससे व्यक्ति और आम जनता दोनों को मदद मिलती है।
- **तापीय स्थिरता: यह कमरे के तापमान पर 9 महीने से अधिक समय तक** स्थिर रहता है , शीत भंडारण के बिना **उष्णकटिबंधीय और दूरदराज के क्षेत्रों में उपयोगी है।**
- **व्यापक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया: कई एंटीजन को** जोड़ती है , जिससे शरीर को **मजबूत, लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा बनाने में मदद मिलती है** ।
- **लागत प्रभावी उत्पादन: लैक्टोकोकस लैक्टिस** का उपयोग **सस्ती और स्केलेबल विनिर्माण** की अनुमति देता है ।

- **लाइसेंसिंग मॉडल:** आईसीएमआर **गैर-अनन्य लाइसेंसिंग की पेशकश करने की योजना बना रहा है** , जिससे **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा** ।
- **राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप: मेक इन इंडिया** पहल और **राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रणनीति का** समर्थन करता है ।

**चुनौतियां**

- **जनजातीय क्षेत्रों में सीमित जागरूकता: मलेरिया से प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों** में , टीकाकरण के बारे में शिक्षा अक्सर **अपर्याप्त होती है** , जिसके कारण टीकाकरण में कमी आती है।
- **वितरण संबंधी मुद्दे: दूरदराज के गांवों में** टीकों के सुरक्षित **परिवहन और वितरण** के लिए उचित बुनियादी ढांचे का अभाव हो सकता है ।
- **टीका स्वीकृति:**

  स्थानीय आबादी के बीच **गलत सूचना या अविश्वास के कारण प्रतिरोध या कम भागीदारी हो सकती है** ।
- **प्रारंभिक चरण में लागत और पैमाना: बड़े पैमाने पर रोलआउट शुरू होने से पहले प्रारंभिक उत्पादन** और वितरण लागत अधिक हो सकती है ।

**आगे बढ़ने का रास्ता**

- **सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा:** उदाहरण: **स्थानीय आशा कार्यकर्ताओं को** स्थानिक जिलों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षित करें।
- **अंतिम-मील वितरण को मजबूत करें:** उदाहरण: जंगली या पहाड़ी इलाकों में **सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज** और **ड्रोन का उपयोग करें।**
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग:** शीघ्रता से पहुंच बढ़ाने के लिए **वैक्सीन निर्माताओं** के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करें ।
- **हॉटस्पॉट्स में पायलट कार्यक्रम:** प्रारंभिक प्रभाव का आकलन करने के लिए ओडिशा या छत्तीसगढ़ में **परीक्षण टीकाकरण** शुरू करना ।

**निष्कर्ष**

**घरेलू, दोहरे चरण वाले टीके का समाधान** प्रदान करके मलेरिया के विरुद्ध भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है । यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों का समर्थन करता है और साथ ही भारत को **उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों** के लिए टीके के विकास में एक **वैश्विक योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करता है। उचित योजना और पहुँच के साथ, यह** संवेदनशील क्षेत्रों में मलेरिया के संचरण और उससे होने वाली मौतों को उल्लेखनीय रूप से **कम कर सकता है।**

## परमाणु ऊर्जा विजन 2047

**प्रसंग**

केंद्रीय बजट 2025-26 में, सरकार ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8.18 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने की साहसिक योजना की घोषणा की, जिसमें 2033 तक लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। यह विकसित भारत विजन और 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के अनुरूप है।

**समाचार के बारे में**

- भारत का लक्ष्य 2047 तक परमाणु ऊर्जा को 100 गीगावाट तक बढ़ाना है।
- 2033 तक एसएमआर विकास के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित।
- परमाणु ऊर्जा को शुद्ध शून्य और ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी माना जाता है।
- योजना को विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप बनाया गया है।

**परमाणु ऊर्जा विजन 2047 की विशेषताएँ**

- लंबा संयंत्र जीवन: परमाणु संयंत्र 50-60 वर्षों तक कुशलतापूर्वक संचालित होते हैं।
- बेस-लोड प्रदाता: आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा के विपरीत, विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करता है।
- एसएमआर निवेश: लचीली तैनाती के लिए स्वदेशी मॉड्यूलर रिएक्टरों पर ध्यान केंद्रित करना।
- पीएचडब्ल्यूआर स्केलिंग: 700 मेगावाट दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों का विस्तार।
- निजी प्रवेश को बढ़ावा: परमाणु ऊर्जा अधिनियम और सीएलएनडीए में संशोधन का प्रस्ताव।
- ग्रीन लेबल: आसान वित्तपोषण के लिए परमाणु ऊर्जा को ग्रीन के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया।

**चुनौतियां**

- सीएलएनडीए बाधाएं: आपूर्तिकर्ता दायित्व खंड विदेशी निवेश (जैसे, अमेरिकी फर्म) को अवरुद्ध करता है।
- विनियामक अंतराल: एईआरबी को वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है; सुरक्षा स्वतंत्रता सीमित है।

- लागत में वृद्धि का जोखिम: फ्रांसीसी और अमेरिकी परियोजनाओं में देरी से आर्थिक चिंताएं बढ़ रही हैं।
- टैरिफ विवाद: चल रहे मामले (जैसे, गुजरात ऊर्जा बनाम एनपीसीआईएल) बिजली बिक्री समझौतों को प्रभावित करते हैं।

**आगे बढ़ने का रास्ता**

- सीएलएनडीए में संशोधन: विदेशी निवेश को सक्षम करने के लिए आपूर्तिकर्ता दायित्व को युक्तिसंगत बनाना।
- वैधानिक नियामक: स्वतंत्र परमाणु निगरानी के लिए एईआरबी को सशक्त बनाना।
- हरित वित्तपोषण पहुंच: जलवायु से जुड़ी निधियों को सुरक्षित करने के लिए परमाणु ऊर्जा को हरित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
- एसएमआर पायलट रोलआउट: सार्वजनिक क्षेत्र से शुरुआत करें, फिर निजी क्षेत्र तक विस्तार करें।

**निष्कर्ष**

2047 तक भारत का परमाणु रोडमैप स्वच्छ, दृढ़ और मापनीय ऊर्जा की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। कानूनी और वित्तीय बाधाओं को दूर करके और एसएमआर जैसी स्वदेशी तकनीकों में निवेश करके, भारत औद्योगिक विकास को जलवायु उत्तरदायित्व के साथ संतुलित कर सकता है, जिससे परमाणु ऊर्जा विकसित भारत की आधारशिला बन सकती है।

## यूनेस्को और संयुक्त राज्य अमेरिका

**प्रसंग**

संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने के मात्र दो साल बाद, दिसंबर 2026 तक इससे बाहर निकलने की अपनी मंशा घोषित की है। अमेरिका ने इस कदम के पीछे यूनेस्को के कथित इज़राइल-विरोधी पूर्वाग्रह और फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के उसके फैसले को प्रमुख कारण बताया है।

**समाचार के बारे में**

- अमेरिका दिसंबर 2026 तक यूनेस्को से बाहर हो जाएगा।
- यूनेस्को के फिलिस्तीन समर्थक रुख के कारण यह कदम उठाया गया।
- यह 2023 में पुनः शामिल होने के केवल दो वर्ष बाद आया है।
- संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के भीतर भू-राजनीतिक तनाव पर प्रकाश डाला गया।

**यूनेस्को के बारे में**

1. **यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो** दुनिया भर में **शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से वैश्विक शांति को** बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है ।
2. **1945 में गठित** यूनेस्को की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी** ।
3. इसके **193 सदस्य देश और 11 सहयोगी सदस्य हैं** , इसका मुख्यालय **पेरिस में है** और विश्व भर में **इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं ।**
4. **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह (यूएनएसडीजी)** का हिस्सा है , जो **सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में मदद करता है** ।
5. यह वैश्विक नीतियों और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** , **वैज्ञानिक सहयोग** , **सांस्कृतिक संरक्षण** और **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।**
6. यूनेस्को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल समावेशन, जलवायु विज्ञान पर **नैतिक मानक निर्धारित करता है** और विश्व भर में **ज्ञान समानता को बढ़ावा देता है।**
7. **यूनेस्को का संस्थापक सदस्य** रहा है और **यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से सक्रिय रूप से काम करता है** ।

**चुनौतियां**

- राजनीतिक प्रभाव: यूनेस्को के निर्णय अक्सर सदस्य-राज्य संघर्षों (जैसे, फिलिस्तीन मुद्दा) को प्रतिबिंबित करते हैं।
- वित्तीय दबाव: अमेरिका इसका प्रमुख वित्तपोषक है; इससे यूनेस्को का बजट कमजोर हो सकता है।
- विश्वसनीयता संबंधी चिंताएं: बार-बार सदस्यता वापस लेने से यूनेस्को की वैश्विक वैधता प्रभावित होती है।
- वैश्विक विभाजन: बहुपक्षीय निकायों में पश्चिमी नेतृत्व पर सवाल उठाता है।

**आगे बढ़ने का रास्ता**

- **तटस्थता को बढ़ावा देना:** यूनेस्को को सदस्य विचारों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए।
- **वित्तपोषण में विविधता लाना:** एकल-राज्य अंशदान पर निर्भरता कम करना।
- **कूटनीति को मजबूत करें:** राजनीतिक अलगाव पर बातचीत को प्रोत्साहित करें।

- **अधिदेश पर ध्यान केंद्रित करें:** शिक्षा और संस्कृति में यूनेस्को की भूमिका को सुदृढ़ करें, न कि भू-राजनीति में।

**निष्कर्ष**

यूनेस्को से अमेरिका का हटना अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के भीतर बढ़ती भू-राजनीतिक दरारों को दर्शाता है। आगे बढ़ते हुए, यूनेस्को को शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से शांति के अपने मूल मिशन को कायम रखना होगा, साथ ही वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक और प्रभावी बने रहने के लिए खुद को राजनीतिक ध्रुवीकरण से अलग रखना होगा।

## भारत-ब्रिटेन ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए

**प्रसंग**

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में एक ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए और **भारत-यूके विज़न 2035 का समर्थन किया** । इस समझौते का उद्देश्य व्यापार, गतिशीलता, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, जलवायु कार्रवाई और रक्षा में सहयोग को गहरा करना है, जिससे भारत-यूके संबंधों को दीर्घकालिक रणनीतिक आधार मिलेगा।

**समझौते के बारे में**

- ब्रिटेन को भारतीय निर्यात के लिए 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य-शुल्क पहुंच।
- समझौते में माल, सेवाएं, गतिशीलता, निवेश और सामाजिक सुरक्षा छूट शामिल हैं।
- एमएसएमई, श्रम-प्रधान क्षेत्रों, तथा महिला एवं युवा उद्यमियों के उत्थान के लिए बनाया गया है।
- विजन 2035 में विकास, प्रौद्योगिकी, रक्षा, जलवायु और शिक्षा में सहयोग की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

**सीईटीए की प्रमुख विशेषताएं**

- **टैरिफ में कमी:** प्रसंस्कृत खाद्य, वस्त्र, चमड़ा और समुद्री उत्पादों के लिए 70% टैरिफ को घटाकर 0% कर दिया गया।
- **व्यावसायिक गतिशीलता:** भारतीय पेशेवरों, विशेषकर आईटी और शिक्षा क्षेत्रों के लिए वीज़ा नियमों में ढील दी गई।
- **सामाजिक सुरक्षा राहत:** भारतीय कामगारों को 3 वर्ष तक ब्रिटेन के सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट मिलेगी।
- **एसएमई समर्थन:** कुशल निर्यात के लिए समर्पित एसएमई चैनल, डिजिटल व्यापार और कागज रहित सीमा शुल्क।
- **सेवा व्यापार:** वित्त, कानून, वास्तुकला और परामर्श में भारतीय सेवाओं को बढ़ावा।
- **बाजार पहुंच:** डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर, ब्रिटेन के 63.4 बिलियन डॉलर के कृषि बाजार में प्रवेश।

**चुनौतियां**

- **संवेदनशील क्षेत्र:** घरेलू हितों की चिंताओं के कारण डेयरी और कृषि को आंशिक रूप से बाहर रखा गया।
- **कार्यान्वयन में विलंब:** पारस्परिक योग्यता मान्यता और वीज़ा प्रणालियों में तकनीकी अड़चनें।
- **भू-राजनीतिक जोखिम:** ब्रिटेन की नीतिगत बदलाव या भारत के चुनावी परिवर्तन नीतिगत निरंतरता को धीमा कर सकते हैं।
- **एमएसएमई की तैयारी:** सक्रिय समर्थन के बिना छोटी कंपनियों के पास वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी हो सकती है।

**आगे बढ़ने का रास्ता**

- जागरूकता अभियान: निर्यात प्रक्रियाओं और डिजिटल व्यापार अनुपालन पर एमएसएमई को प्रशिक्षित करना।
- संस्थागत तंत्र: सेवाओं में तकनीकी बाधाओं से निपटने के लिए संयुक्त नियामक बोर्ड स्थापित करें।
- क्षेत्रीय योजनाएं: खाद्य और परिधान जैसे यूके-विशिष्ट निर्यात क्षेत्रों के लिए पीएलआई जैसे प्रोत्साहन लागू करना।
- शैक्षणिक साझेदारियां: भविष्य की नौकरी की मांगों को पूरा करने के लिए दोहरी डिग्री और हरित कौशल पहल को तेजी से आगे बढ़ाना।

**निष्कर्ष**

भारत-यूके सीईटीए और विज़न 2035 द्विपक्षीय सहयोग में एक रणनीतिक छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यापार उदारीकरण, गतिशीलता, जलवायु लक्ष्यों और तकनीकी नवाचार को एकीकृत करके, यह समझौता न केवल भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देता है, बल्कि समावेशी विकास, विशेष रूप से युवाओं, एमएसएमई और कुशल पेशेवरों के लिए, भी सुनिश्चित करता है।

## राष्ट्रीय सहकारी नीति – 2025

**संदर्भ:**

राष्ट्रीय **सहकारिता नीति - 2025 का** औपचारिक शुभारंभ **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा नई दिल्ली** में किया गया , जो भारत के सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। यह नीति सहकारी क्षेत्र को **संस्थागत, आधुनिक और लोकतांत्रिक बनाने के व्यापक**

**राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है** , जो लंबे समय से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना का एक आधारभूत स्तंभ रहा है। यह नीति सहकारी मॉडल को न केवल एक विरासत प्रणाली के रूप में, बल्कि **ग्रामीण सशक्तिकरण, डिजिटल एकीकरण और समावेशी विकास के लिए एक भविष्य-तैयार माध्यम के रूप में देखती है** ।

**राष्ट्रीय सहकारी नीति – 2025 के प्रमुख उद्देश्य**

- संरचनात्मक सुधारों और विस्तार के माध्यम से 2034 तक
  **सहकारी क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को तिगुना करना ।**
- **कम से कम 50 करोड़ नागरिकों को** सहकारी सदस्यों के रूप में शामिल करना सुनिश्चित करना, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े सहभागी आंदोलनों में से एक बन सके।
- ग्रामीण विकास को गति देने के लिए **प्रत्येक गांव में सहकारी समिति की स्थापना करें ।**
- **डिजिटल शासन को बढ़ावा देना** , वित्तीय पारदर्शिता में सुधार करना और जवाबदेही बढ़ाना।
- सहकारिता-संचालित आजीविका के माध्यम से **अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समुदायों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और युवाओं को सशक्त बनाना ।**
- इंडिया@100 (2047) तक सहकारी समितियों का **एक आत्मनिर्भर, रोजगार-समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना ।**

**राष्ट्रीय सहकारी नीति – 2025 की मुख्य विशेषताएं**

**1. समावेशी, ग्रामीण-केंद्रित विकास मॉडल**

- ग्रामीण विकास इंजन के रूप में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना; सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियां; प्रत्येक तहसील में पांच आदर्श सहकारी गांवों की योजना बनाई गई।

**2. सहकारी समितियों का तीव्र विस्तार और आधुनिकीकरण**

- सहकारी समितियों में 30% वृद्धि का लक्ष्य; 45,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थापित करने का कार्य प्रगति पर; पर्यटन, टैक्सी, ऊर्जा, बीमा क्षेत्रों को बढ़ावा; सहकार टैक्सी का शुभारंभ।

**3. प्रौद्योगिकी-संचालित शासन और कानूनी सुधार**

- प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी कम्प्यूटरीकरण, क्लस्टर-आधारित निगरानी, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस और 10-वर्षीय कानूनी समीक्षा तंत्र के माध्यम से वास्तविक समय डिजिटल शासन को सक्षम बनाता है।

**4. महिला एवं युवा सशक्तिकरण मुख्य स्तंभ**

- त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना; श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ; युवा उद्यमिता को बढ़ावा; महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के लिए नेतृत्व की भूमिका सुनिश्चित करना।

**5. क्षेत्रीय विविधीकरण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण**

- रसद, पर्यटन, जैविक, ऊर्जा में सहकारी प्रवेश को बढ़ावा देता है; निर्यात, बीज, और जैविक उत्पाद बहु-राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना करता है।

**6. स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण**

- हरित प्रौद्योगिकी और वृत्तीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना; निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी भागीदारी के माध्यम से वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देना।

**निष्कर्ष**

राष्ट्रीय **सहकारी नीति - 2025** केवल एक सुधार पहल नहीं है; यह एक **संरचनात्मक परिवर्तन एजेंडा है** । इसका उद्देश्य **सहकारी संस्थाओं को** आधुनिक, तकनीक-प्रेमी और समावेशी बनाकर उन्हें भारत के व्यापक आर्थिक आख्यान में मुख्यधारा में लाना है। **भारत@2047 तक विस्तारित एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण के साथ** , यह नीति ग्रामीण विकास को पुनर्परिभाषित कर सकती है, आर्थिक लोकतंत्र को गहरा कर सकती है, और कॉर्पोरेट पूंजीवाद का एक लचीला विकल्प प्रस्तुत कर सकती है—जो पारस्परिक लाभ, सामाजिक समता और स्थानीय सशक्तिकरण पर आधारित है।

## नदियों को आपस में जोड़ना

**संदर्भ**

जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) पर नवीनतम अद्यतन प्रकाशित किया है, जिसमें केन-बेतवा परियोजना और बाढ़ नियंत्रण प्रयासों जैसी प्रमुख नदी जोड़ पहलों को शामिल किया गया है।

**राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी):**

इस दीर्घकालिक योजना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों तक जल पहुंचाकर जल की उपलब्धता को संतुलित करना है।

कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) नदी संपर्कों के लिए प्रस्ताव तैयार करती है, व्यवहार्यता विश्लेषण करती है, तथा परियोजना रिपोर्ट का मसौदा तैयार करती है।

**एनपीपी की संरचना:**

कुल नदी जोड़ो प्रस्ताव: 30

दो समूहों में विभाजित:

- हिमालयन घटक – 14 लिंक
- प्रायद्वीपीय घटक – 16 लिंक

केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी):

- नदी जोड़ो परियोजना का पहला कार्यान्वयन शुरू
- विशेष निकाय का गठन: केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए)
- वर्तमान स्थिति: दौधन बांध घटक के लिए कार्य स्वीकृत कर दिया गया है

**कोसी-मेची अंतर-राज्य लिंक परियोजना**

- यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत स्वीकृत की गई है , जिसका लक्ष्य पुरानी सिंचाई योजनाएं हैं।
- जिम्मेदार मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय

**कवरेज क्षेत्र:**

बिहार में बाढ़ से प्रभावित चार जिले- अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार परियोजना के बारे में इसमें पूर्वी कोसी मुख्य नहर (ईकेएमसी) का पुनः डिजाइन तैयार करना और इसे बिहार में मेची नदी से जोड़ना शामिल है। इसका लक्ष्य एक ही राज्य के भीतर नदी घाटियों के बीच जल हस्तांतरण को सक्षम बनाना है। पूरा होने की समय-सीमा: परियोजना का पूरा होना मार्च 2029 तक लक्षित है।

**फ़ायदे:**

- 2.15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
- बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में
- उत्तर बिहार में कृषि उपज में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद

**निष्कर्ष:**

नदियों को जोड़ने की पहल का उद्देश्य समान जल वितरण सुनिश्चित करना, सिंचाई को बढ़ावा देना और बाढ़ को कम करना है। अधिशेष और घाटे वाले बेसिनों को जोड़कर, केन-बेतवा और कोसी-मेची जैसी परियोजनाएँ भावी पीढ़ियों के लिए टिकाऊ कृषि, क्षेत्रीय विकास और जल सुरक्षा का वादा करती हैं।

## महिला शतरंज विश्व कप

**संदर्भ (20-25 शब्द):**

भारत का शतरंज परिदृश्य **जुलाई 2025 में एक मील के पत्थर पर पहुंच गया** , जब **दिव्या देशमुख ने महिला शतरंज विश्व कप** जीता , और भारत को **FIDE विश्व कप 2025 का मेजबान भी घोषित किया गया** ।

**समाचार के बारे में:**

• दिव्या देशमुख ने **जॉर्जिया** में **आयोजित FIDE महिला विश्व कप 2025 जीता** ।

• वह **भारत की 88वीं ग्रैंडमास्टर बनीं** । • भारत 30 अक्टूबर से **27 नवंबर तक FIDE शतरंज विश्व कप 2025** की मेज़बानी करेगा ।

**अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE)**

1. एफआईडीई (FIDE) अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, जो शतरंज के लिए वैश्विक नियामक संस्था है।
2. 1924 में स्थापित, FIDE का आदर्श वाक्य "Gens una Sumus" है, जिसका अर्थ है "हम एक परिवार हैं"।
3. यह संगठन विश्व शतरंज चैंपियनशिप और शतरंज ओलंपियाड के आयोजन के लिए जिम्मेदार है।
4. एफआईडीई शतरंज प्रतियोगिता के लिए मानकीकृत नियम, विनियम और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली स्थापित करता है।
5. ग्रैंडमास्टर और इंटरनेशनल मास्टर जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खिताब FIDE द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

**फिडे विश्व कप 2025 :**

• **FIDE विश्व कप 2025 में 206 खिलाड़ी** नॉकआउट **प्रारूप में** भाग लेंगे ।

• प्रत्येक दौर में **दो क्लासिकल गेम होंगे** , और **यदि आवश्यक हो तो टाई-ब्रेक भी होंगे** ।

• **शीर्ष 50 खिलाड़ियों को** बाई मिलेगी; बाकी रिवर्स पेयरिंग में खेलेंगे।
• **शीर्ष 3 खिलाड़ी 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट** के लिए क्वालीफाई करेंगे ।
• भारत का **शतरंज बुनियादी ढांचा टाटा स्टील शतरंज इंडिया** जैसे आयोजनों के साथ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है ।
• भारत ने **FIDE ओलंपियाड 2022** और **विश्व जूनियर अंडर-20 चैम्पियनशिप 2024 की मेजबानी की है** ।

**निष्कर्ष :**

**दिव्या देशमुख की ऐतिहासिक जीत** और भारत द्वारा 2025 **विश्व कप की मेजबानी के** साथ , राष्ट्र एक **शतरंज महाशक्ति के रूप में उभर रहा है** , जिसमें विरासत, प्रतिभा और वैश्विक मान्यता का सम्मिश्रण है।

## चोल साम्राज्य

**प्रसंग :**

**राजेंद्र चोल प्रथम** की जयंती पर , **भारत के प्रधानमंत्री ने गंगईकोंडा चोलपुरम** में चोल राजवंश की **समुद्री शक्ति** , शासन **और** सांस्कृतिक **एकता की विरासत का** जश्न मनाया ।

**समाचार के बारे में:**

• प्रधानमंत्री **ने स्मारक सिक्के जारी किए** और राजेंद्र एवं राजराजा चोल की **प्रतिमाओं की घोषणा की ।**

• **नौसेना विस्तार** और **स्थानीय लोकतंत्र** में चोलों की भूमिका को याद किया ।

• संस्कृति और व्यापार के माध्यम से **दक्षिण पूर्व एशिया में** उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला ।

• प्रधानमंत्री ने **आदि तिरुत्तरी उत्सव में भाग लिया** और विरासत को वर्तमान राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा।

**चोल वंश के प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियाँ:**

- **राजराजा चोल प्रथम (985-1014 ई.): उन्होंने चोल नौसेना बलों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तंजावुर में** भव्य बृहदीश्वर मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया और श्रीलंका के उत्तरी भागों में साम्राज्य की पहुंच को सफलतापूर्वक बढ़ाया।
- **राजेंद्र चोल प्रथम (1014-1044 ई.):** अपने महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों के लिए प्रसिद्ध, वे गंगा के मैदानों तक आगे बढ़े, **गंगईकोंडा चोलपुरम शहर की स्थापना की,** और मलेशिया, इंडोनेशिया और मालदीव जैसे क्षेत्रों सहित दक्षिण पूर्व एशिया में चोल प्रभाव का प्रक्षेपण किया।
- **कुलोत्तुंग चोल प्रथम:** उनके शासनकाल में प्रशासनिक दक्षता और भूमि राजस्व प्रणालियों में सुधारों पर जोर दिया गया, जिससे आंतरिक स्थिरता और आर्थिक मजबूती की चोल विरासत को बनाए रखने में मदद मिली।

**चोल साम्राज्य की विशेषताएँ:**

• **कुदावोलाई प्रणाली ने** ताड़ के पत्तों पर मतपत्रों का उपयोग करके
**ग्राम-स्तरीय चुनावों को** सक्षम बनाया ।

• **विकेन्द्रीकृत सभाएँ** (उर, सभा, नगरम) भूमि, कर और न्याय के मामलों को संभालती थीं।
• साम्राज्य भर में **कुशल अभिलेखों , सर्वेक्षणों और राजस्व अभिलेखों को बनाए रखा।**

• एक **शक्तिशाली नौसेना थी** , जिसका विस्तार **श्रीलंका** और **दक्षिण-पूर्व एशिया में था** ।

• **नागपट्टिनम** और **पूम्पुहार** जैसे बंदरगाहों के माध्यम से **मंदिर अर्थव्यवस्थाओं और व्यापार को** प्रोत्साहित किया ।

• **शैव और वैष्णव** दोनों धर्मों का समर्थन किया , **धार्मिक सद्भाव** और मंदिर नेटवर्क को बढ़ावा दिया।

**निष्कर्ष :**

चोल **साम्राज्य सुशासन** , **समुद्री उत्कृष्टता** और **सांस्कृतिक विस्तार** का प्रतीक रहा है । इसकी विरासत भारत को **ऐतिहासिक गौरव** और **आधुनिक राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा प्रदान करती है** ।

## सोहराई कला

**संदर्भ:**
झारखंड की सोहराय चित्रकला ने राष्ट्रपति भवन में *कला उत्सव 2025 के दौरान राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जहां भारत के राष्ट्रपति ने इसे भारत के सांस्कृतिक सार का सच्चा प्रतिबिंब बताते हुए इसकी प्रशंसा की।*

**सोहराय क्या है?**

- सोहराई झारखंड के **संथाल, मुंडा और उरांव समुदायों द्वारा निभाई जाने वाली एक आदिवासी दीवार-चित्रकारी** परंपरा है । महिला कलाकार प्राकृतिक रंगों और हस्तनिर्मित औजारों का उपयोग करके अपने घरों की मिट्टी की दीवारों को सजाती हैं, जो ग्रामीण जीवन और रीति-रिवाजों में गहराई से निहित एक परंपरा को जारी रखती है।
- यह कला फसल कटाई के मौसम के आसपास बनाई जाती है,

**सोहराय कला की उल्लेखनीय विशेषताएं:**

- **प्रकृति से विषयवस्तु:** कलाकृति में **पशु, पक्षी, पत्ते और ग्रामीण जीवन को दर्शाया गया है, जो** पर्यावरण

और कृषि समाज की लय के साथ सामंजस्य व्यक्त करता है।

- **प्राकृतिक रंगों का प्रयोग:** कलाकार स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों जैसे लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी, काले पत्थर के पाउडर और पीली मिट्टी पर निर्भर करते हैं, जिससे यह कार्य पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ हो जाता है।
- **पारंपरिक उपकरण:** आधुनिक ब्रशों के स्थान पर, महिलाएं रंग लगाने के लिए बांस की टहनियों, चबाने वाली लकड़ियों और कपड़े के टुकड़ों का उपयोग करती हैं।
- **महिला-केन्द्रित परंपरा:** महिलाओं की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित यह कला सांस्कृतिक वाहक और सृजनकर्ता के रूप में महिलाओं की भूमिका को दर्शाती है।
- **अनुष्ठानों से जुड़े:** ये भित्तिचित्र केवल सजावट से कहीं अधिक हैं - ये आध्यात्मिक अवसरों को दर्शाते हैं, भूमि की उर्वरता का जश्न मनाते हैं, तथा पशुधन और फसलों के प्रति कृतज्ञता दर्शाते हैं।

**निष्कर्ष:**

सोहराई कला लोगों, ज़मीन और आध्यात्मिकता के बीच एक स्थायी जुड़ाव का प्रतीक है। यह पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली, मौखिक विरासत और स्त्री अभिव्यक्ति का प्रतीक है। प्रतीकात्मक डिज़ाइनों और मौसमी लय के माध्यम से, यह दुनिया को देखने और उसका जश्न मनाने के सदियों पुराने तरीके को जीवित रखती है।

## अमेरिका ने भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाया

**प्रसंग**

अमेरिका ने व्यापार असंतुलन और रूस के साथ भारत के निरंतर ऊर्जा और रक्षा संबंधों का हवाला देते हुए भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाया।

**समाचार के बारे में**

- अगस्त 2025 से अमेरिका को निर्यात किये जाने वाले भारतीय सामानों पर 25% शुल्क लगेगा।
- रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025 से संबंधित दंड, रूस के साथ व्यापार करने वाले राष्ट्रों को लक्षित करता है।
- भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के पांचवें दौर की विफलता के बाद यह कदम उठाया गया है।
- भारत ने अपने निष्पक्ष व्यापार रिकॉर्ड का बचाव करने के लिए ब्रिटेन के साथ अपने मुक्त व्यापार समझौते का हवाला दिया।

**टैरिफ के प्रमुख प्रावधान**

- यह कपड़ा, फार्मा और इंजीनियरिंग निर्यात जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर लागू होता है।
- रूस से संबंधित रक्षा और ऊर्जा संबंधों को प्रतिबंधों की अवहेलना के रूप में देखा जा रहा है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा उद्धृत "घृणित" व्यापार बाधाओं पर आधारित।
- अप्रैल 2025 में पहले घोषित निलंबित 26% टैरिफ को बहाल किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा।
- प्रस्तावित रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025 के माध्यम से विधायी समर्थन लंबित है।
- भारत का मंत्रालय किसानों और एमएसएमई पर टैरिफ के प्रभाव की समीक्षा कर रहा है।

**चुनौतियां**

- अमेरिकी बाजार में निर्यात घाटा, विशेषकर कपड़ा और फार्मा क्षेत्र में।
- क्वाड के भीतर कूटनीतिक तनाव, भारत-प्रशांत सहयोग पहल को खतरे में डाल रहा है।
- भारत की सामरिक स्वायत्तता, विशेषकर रूस के साथ ऊर्जा सौदों पर दबाव।
- आपूर्ति श्रृंखला का जोखिम भारत से हटकर वियतनाम जैसे सस्ते प्रतिस्पर्धियों की ओर स्थानांतरित हो रहा है।

**आगे बढ़ने का रास्ता**

- अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ और आसियान को निर्यात में विविधता लाना।
- अधिमान्य पहुंच पुनः प्राप्त करने के लिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए को तीव्र गति से आगे बढ़ाना।
- भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को पुनर्जीवित करने और टैरिफ कम करने के लिए कूटनीतिक रूप से संलग्न होना।
- बहुपक्षवाद की पुनः पुष्टि करना, विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप व्यापार प्रथाओं में भारत की भूमिका को प्रदर्शित करना।

**निष्कर्ष**

भारत को अपने सामरिक हितों को व्यापार कूटनीति के साथ संतुलित करना होगा, तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि बाहरी दबाव उसकी आर्थिक संप्रभुता या निष्पक्ष एवं पारस्परिक व्यापार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को कमजोर न करें।

## क्लुचेव्स्कॉय ज्वालामुखी

**संदर्भ:**

रूस के क्लुचेव्स्कॉय ज्वालामुखी ने उस समय वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जब उसके निकट 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे टेक्टोनिक रूप से सक्रिय कामचटका क्षेत्र में तीव्र भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधि का पता चला।

**क्ल्युचेव्स्कॉय ज्वालामुखी:**

क्ल्युचेव्स्कॉय, जिसे क्ल्युचेव्स्काया सोपका भी कहा जाता है, एक क्लासिक स्ट्रैटोज्वालामुखी है जो अपने तेजी से बढ़ते शंकु और निरंतर विस्फोटों के लिए जाना जाता है।

- **स्थान:** यह पूर्वी रूस में कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है, जो बेरिंग सागर से लगभग 100 किमी दूर है।
- **टेक्टोनिक सेटिंग:** यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो भूगर्भीय रूप से सक्रिय बेल्ट है जहां कई भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं।
- **विस्फोट का इतिहास:** प्रलेखित विस्फोटों का इतिहास 1697 का है, और तब से यह लगातार सक्रिय रहा है।
- **विरासत महत्व:** यह ज्वालामुखी यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध "कामचटका के ज्वालामुखी" विश्व विरासत स्थल की एक प्रमुख विशेषता है।

**ज्वालामुखियों के प्रकार**

1. **स्ट्रेटोवोलकैनो (संयुक्त ज्वालामुखी):**
   - संरचना: ऊंची, खड़ी और शंकाकार।
   - परतें: लावा, राख और चट्टान की वैकल्पिक परतों से निर्मित।
   - लावा प्रकार: चिपचिपा और अम्लीय (उच्च सिलिका), जिससे विस्फोटक विस्फोट होता है।
   - उदाहरण: माउंट फूजी (जापान), माउंट वेसुवियस (इटली), क्ल्युचेव्स्कॉय (रूस)।
   - खतरे: पाइरोक्लास्टिक प्रवाह, राख गिरना, और हिंसक विस्फोट।
2. **कवच ज्वालामुखी:**
   - संरचना: चौड़ा, धीरे से ढलान वाला गुंबद आकार।
   - लावा का प्रकार: पतला, बहता हुआ बेसाल्टिक लावा (कम सिलिका), बड़े क्षेत्रों में बहता है।
   - विस्फोट शैली: गैर-विस्फोटक, शांत विस्फोट।
   - उदाहरण: मौना लोआ और मौना केआ (हवाई), आइसलैंडिक ज्वालामुखी।
   - खतरे: लावा प्रवाह, कम राख या पाइरोक्लास्टिक पदार्थ।

**कामचटका प्रायद्वीप:**

सुदूर पूर्वी रूस में स्थित कामचटका एक विशाल और ऊबड़-खाबड़ भूभाग है, जिसकी सीमा पश्चिम में ओखोटस्क सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर/बेरिंग सागर से लगती है।

**पारिस्थितिकी और जलवायु:**

- **वनस्पति क्षेत्र:** ऊपरी क्षेत्र टुंड्रा वनस्पति को सहारा देते हैं - जिनमें अधिकतर काई, लाइकेन और कामचटका एल्डर जैसी बौनी झाड़ियाँ होती हैं।
- **वन बेल्ट:** निचले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्च, लार्च, चिनार और विलो प्रजातियों के वन हैं।
- **जलवायु पैटर्न:** इस क्षेत्र में उप-आर्कटिक जलवायु पाई जाती है, जिसमें लंबी, बर्फीली सर्दियां और छोटी, नम गर्मियां होती हैं।

## बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025

**संदर्भ: भारतीय बैंकिंग कानून में एक नया संशोधन, बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025** प्रभावी होगा ।

**अधिनियम के बारे में: वित्त मंत्रालय** द्वारा प्रस्तुत यह संशोधन, लंबे समय से चली आ रही नियामक कमियों को दूर करने के लिए **पाँच प्रमुख बैंकिंग कानूनों में संशोधन करता है। इसका मुख्य लक्ष्य** वाणिज्यिक और सहकारी दोनों बैंकों में अधिक **पारदर्शिता, जमाकर्ताओं की सुरक्षा** और **संस्थागत जवाबदेही** सुनिश्चित करना है।

**संशोधन के प्राथमिक लक्ष्य:**

- बैंकों में प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करें।
- जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखापरीक्षा प्रथाओं को उन्नत करना।
- सहकारी बैंकिंग विनियमों को संवैधानिक सिद्धांतों के साथ सुसंगत बनाना।

**अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं:**

1. **'पर्याप्त हित' की संशोधित परिभाषा:** बैंकिंग कंपनी में 'पर्याप्त हित' रखने के लिए मौद्रिक सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर **2 करोड़ रुपये कर दिया गया है** , जो 1968 से वर्तमान मुद्रास्फीति के स्तर और वित्तीय विकास के अनुरूप है।
2. **सहकारी बैंकों में निदेशक का कार्यकाल:** बोर्ड के सदस्यों (अध्यक्षों और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर) का कार्यकाल अब 8 से बढ़ाकर **10 वर्ष कर दिया गया है, जिससे यह प्रावधान** सहकारी क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से किए गए **97वें संविधान संशोधन** के अनुरूप हो गया है ।
3. **IEPF में दावा रहित परिसंपत्तियों का स्थानांतरण:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) अब दावा रहित लाभांश, बांड परिपक्वता और अन्य उपकरणों को **निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे कंपनी अधिनियम** के समान परिसंपत्ति वसूली तंत्र को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा ।
4. **उन्नत लेखापरीक्षा निरीक्षण: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वैधानिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का** निर्णय लेने की अनुमति दी गई है , जिससे **उच्च गुणवत्ता वाली लेखापरीक्षा फर्मों** की नियुक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा लेखापरीक्षा कार्यों में **अधिक स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।**
5. **रिजर्व बैंक को रिपोर्टिंग समय-सारिणी में ढील:** भारतीय रिजर्व बैंक को पहले अनिवार्य साप्ताहिक रिपोर्ट के स्थान पर अब लचीली **पाक्षिक, मासिक या त्रैमासिक** रिपोर्टिंग समय-सारिणी लागू कर दी गई है, जिससे अनुपालन बोझ कम होगा और डेटा की गुणवत्ता भी बनी रहेगी।

**भारत के बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है:**

- **विनियामक आधुनिकीकरण:** ये परिवर्तन पुराने प्रावधानों को अद्यतन करते हैं - जिनमें से कई 50 से अधिक वर्ष पुराने हैं - ताकि वे आज की वित्तीय प्रणाली की वास्तविकताओं के अनुरूप हों।
- **सहकारी बैंकों में बेहतर प्रशासन:** संवैधानिक सुधारों को शामिल करके, यह अधिनियम सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में अधिक लोकतांत्रिक और जवाबदेह प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
- **जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ाना:** बेहतर परिसंपत्ति वसूली और मजबूत लेखा परीक्षा मानकों को सुनिश्चित करने से जमाकर्ताओं के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण होता है।

**कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**

1. **ग्रामीण बैंकों में सीमित लेखापरीक्षा क्षमता:** छोटे शहरों में सहकारी बैंकों को वित्तीय या तार्किक बाधाओं के कारण योग्य लेखापरीक्षकों को आकर्षित करने में कठिनाई हो सकती है।
2. **विनियामक तत्परता:** बैंकों को, विशेष रूप से क्षेत्रीय या सहकारी स्तर पर, नई रिपोर्टिंग और शासन ढांचे को लागू करने में **बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण संबंधी अंतराल का सामना करना पड़ सकता है।**
3. **कार्यकाल में परिवर्तन का विरोध:** विस्तारित कार्यकाल को अधिक बार बोर्ड स्तर पर रोटेशन या लोकतांत्रिक परिवर्तन के पक्षधर हितधारकों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
4. **परिसंपत्ति हस्तांतरण जटिलता:** दावा न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान करना और उन्हें IEPF में स्थानांतरित करना कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है, विशेष रूप से पुराने या निष्क्रिय खातों के लिए।

**निष्कर्ष:**

बैंकिंग **कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025** भारत के वित्तीय नियामक ढाँचे को अद्यतन करने की दिशा में एक साहसिक कदम है। पुराने प्रावधानों को समाप्त करके और बैंकों को आधुनिक प्रशासनिक उपकरणों से सशक्त बनाकर, यह अधिनियम जनता का विश्वास, विशेष रूप से सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र के बैंकों में, मज़बूत करने का वादा करता है। हालाँकि, इसकी सफलता **प्रभावी कार्यान्वयन** , **क्षमता निर्माण** और **निरंतर नियामक निगरानी पर निर्भर करेगी** । यदि इसे अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाता है, तो यह भारत के बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय पारदर्शिता और जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

RACE IAS

# करेंट अफेयर्स (MCQ) अभ्यास सेट

1. भारत के मसाला क्षेत्र के संदर्भ में, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है?

   (a) यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक निजी उद्योग-प्रधान निकाय है।

   (b) यह केंद्रीय मंत्रालयों से स्वतंत्र रूप से संचालित एक वैधानिक बोर्ड है।

   (c) यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन बहु-मंत्रालयी समन्वय के साथ कार्य करता है।

   (d) यह पूर्णतः भारतीय मसाला बोर्ड के अधीन कार्य करता है।

2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक हल्दी उत्पादन में भारत के योगदान को सही ढंग से दर्शाता है?

   (a) लगभग 40%, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का निर्यात

   (b) लगभग 60%, 20 से अधिक देशी किस्मों के साथ

   (c) 50% से कम लेकिन जैविक हल्दी उत्पादन में अग्रणी

   (d) 75% से अधिक, 2030 तक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य

3. एनईपी 2020 के अनुसार, प्रस्तावित अकादमिक ऋण बैंक (एबीसी) का क्या कार्य है?

   (a) वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना

   (b) शैक्षणिक गतिशीलता के लिए क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करना

   (c) उच्च शिक्षा में अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तपोषित करना

   (d) स्कूल स्तर की बोर्ड परीक्षाओं के स्थान पर ऑनलाइन परीक्षाएँ आयोजित करना

4. हांगकांग कन्वेंशन (HKC) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा इसके प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

   (a) जहाजों का सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना

   (b) सभी विकासशील देशों में जहाज तोड़ने पर प्रतिबंध लगाना

   (c) क्रूज पर्यटन और समुद्री नौवहन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना

   (d) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों को विनियमित करना

5. ELI योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

   (a) यह ₹1 लाख प्रति माह से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।

   (b) यह पहली बार अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 की प्रत्यक्ष वेतन सहायता प्रदान करती है।

   (c) प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए EPFO पंजीकरण वैकल्पिक है।

   (d) यह योजना केवल IT क्षेत्र की निजी कंपनियों पर लागू होती है।

6. निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियाँ डिजिटल अपनाने के आदेशों के कार्यान्वयन से सीधे संबंधित हैं?

   (a) हेग कन्वेंशन के तहत CARA की कानूनी स्थिति

   (b) CARINGS पोर्टल पर माता-पिता का विवरण संग्रहीत

   (c) नए नियमों के बावजूद राज्य के अधिकारी हार्ड कॉपी पर ज़ोर दे रहे हैं

   (d) शहरी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों की संख्या

7. RDI योजना के तहत विशेष प्रयोजन निधि (SPF) का क्या कार्य है?

   (a) यह विदेशों में पीएचडी शोध के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है

   (b) यह अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण के लिए द्वितीय-स्तरीय प्रबंधकों को धन आवंटित करती है

   (c) यह अनुसंधान उपकरणों की प्रत्यक्ष खरीद का प्रबंधन करती है

   (d) यह नए आविष्कारों के लिए पेटेंट दाखिल करने को नियंत्रित करती है

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

   कथन 1: डार्क वेब को क्रोम या फ़ायरफ़ॉक्स जैसे मानक ब्राउज़रों का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है।

   कथन 2: डार्क वेब पर वेबसाइटें आमतौर पर ".onion" डोमेन का उपयोग करती हैं और गुमनामी बनाए रखने के लिए एन्क्रिप्टेड संचार प्रदान करती हैं।

   उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

   कथन 1: राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेश में स्नातक की पढ़ाई कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का समर्थन करने के लिए लागू की गई है।

   कथन 2: इस योजना के अंतर्गत, केवल QS के शीर्ष 500 रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त छात्र ही पात्र हैं।

RACE IAS

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) को प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

कथन 2: नवीनतम एसआरएस आंकड़ों के अनुसार, सशक्त कार्रवाई समूह (ईएजी) के राज्यों ने केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों की तुलना में बेहतर मातृ स्वास्थ्य परिणाम दर्ज किए हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) सभी नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

कथन 2: केन-बेतवा लिंक परियोजना, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली पहली नदी अंतर्योजन पहल है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: राष्ट्रीय सहकारी नीति - 2025 का लक्ष्य वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद में सहकारी क्षेत्र के योगदान को तीन गुना बढ़ाना है।

कथन 2: नीति का लक्ष्य 2034 तक कम से कम 50 करोड़ नागरिकों को सहकारी सदस्यों के रूप में शामिल करना है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: CETA के तहत, भारतीय पेशेवरों को पाँच वर्षों तक यूके के सामाजिक सुरक्षा अंशदान का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।

कथन 2: यह समझौता भारत को डेयरी उत्पादों सहित पूरे यूके कृषि बाजार तक शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: प्रतिभा सेतु उन उम्मीदवारों की भर्ती की अनुमति देता है जिन्होंने केवल यूपीएससी के लिए आवेदन किया है, लेकिन किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं।

कथन 2: इस पहल को मूल रूप से 2018 में सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के रूप में शुरू किया गया था और 2024 में इसका नाम बदल दिया गया।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: अमेरिका ने यूनेस्को के इज़राइल समर्थक रुख का हवाला देते हुए 2026 में यूनेस्को से अपनी वापसी की घोषणा की।

कथन 2: यह पहली बार होगा जब अमेरिका यूनेस्को से बाहर निकलेगा।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (CLNDA) ने आपूर्तिकर्ता दायित्व प्रावधानों के कारण विदेशी निवेश को बाधित किया है।

कथन 2: परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) पूर्ण कानूनी स्वतंत्रता वाला एक वैधानिक निकाय है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: एडफाल्सीवैक्स एक एकल-चरण मलेरिया टीका है जो परजीवी के केवल यकृत चरण को लक्षित करता है।

कथन 2: इस टीके में तापीय स्थिरता है, जो कमरे के तापमान पर नौ महीने से अधिक समय तक प्रभावी रहता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

18. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन से सतत विकास लक्ष्य (SDG) सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले हैं और जिनमें तत्काल निवेश की आवश्यकता है?

1. सतत विकास लक्ष्य 2 - शून्य भुखमरी

2. सतत विकास लक्ष्य 4 - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

3. सतत विकास लक्ष्य 8 - सभ्य कार्य और आर्थिक विकास

4. सतत विकास लक्ष्य 13 - जलवायु कार्रवाई

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

19. ब्लैक होल विलय घटना GW231123 को मौजूदा तारकीय विकास सिद्धांतों के लिए एक चुनौती क्यों माना जाता है?

(a) इसका पता गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं के उपयोग के बिना लगाया गया था।

(b) इसमें न्यूट्रॉन तारे के पतन से उत्पन्न ब्लैक होल शामिल थे।

(c) विलय करने वाले ब्लैक होल सैद्धांतिक रूप से निषिद्ध "द्रव्यमान अंतराल" श्रेणी में आते हैं।

(d)। यह घटना हमारी आकाशगंगा के भीतर घटित हुई, जो वर्तमान मॉडलों के विपरीत है।

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल मिलाकर प्रतिवर्ष दर्ज की जाने वाली सभी दहेज हत्याओं का 20% से भी कम हिस्सा होता है।

कथन 2: प्रमुख भारतीय शहरों में दहेज से होने वाली मौतों में से लगभग एक-तिहाई अकेले दिल्ली में होती हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

21. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: भारत अपने कच्चे तेल का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा रूस से आयात करता है, मुख्यतः मूल्य लाभ के कारण।

कथन 2: रूसी प्रतिबंध अधिनियम में एक प्रावधान शामिल है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को इसके प्रवर्तन में छह महीने तक की देरी करने की अनुमति देता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में एक वर्ष में सर्वाधिक नागरिक भागीदारी वाले शहरों को पुरस्कृत करने के लिए "सुपर स्वच्छ लीग" नामक एक नई श्रेणी शुरू की गई।

कथन 2: इंदौर और नवी मुंबई जैसे शहरों को वर्षों से उनके निरंतर स्वच्छता प्रदर्शन के लिए इस श्रेणी में मान्यता दी गई।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: विश्व असमानता डेटाबेस (WID) के अनुसार, भारत की आय असमानता विश्व स्तर पर सबसे कम है।

कथन 2: WID के अनुसार, भारत का धन गिनी गुणांक, उसकी आय गिनी गुणांक से काफी अधिक है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: ETLD HCM एक रैमजेट इंजन का उपयोग करता है और मैक 5 तक की गति प्राप्त करता है।

कथन 2: यह मिसाइल केवल परमाणु हथियार ले जा सकती है और इसकी मारक क्षमता 1,500 किमी है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

25. निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूसी तेल आयात करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत पर प्रस्तावित 500% अमेरिकी टैरिफ के संभावित आर्थिक प्रभाव को सबसे अच्छी तरह से समझाता है?

(a) यह कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और घरेलू उत्पादन को तुरंत बढ़ावा देगा।

(b) रूसी तेल की कम माँग के कारण वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट आएगी।

(c) यह भारत के आयात बिल को बढ़ा सकता है और चालू खाता घाटा बढ़ा सकता है।

(d) इसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत के पास बड़े रणनीतिक तेल भंडार हैं।

26. भारत के टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में प्रयुक्त बीपीएएल उपचार पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: बीपीएएल उपचार पद्धति दवा-प्रतिरोधी टीबी के उपचार की अवधि को 24 महीने से घटाकर 6 महीने कर देती है।

कथन 2: इसमें बेडाक्विलाइन, प्रीटोमैनिड और लाइनज़ोलिड दवाओं का संयोजन होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

27. उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसके तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने डार्कनेट के ज़रिए चल रहे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफ़ाश किया?

(a) ऑपरेशन एप्पल

(b) ऑपरेशन स्टॉर्म

(c) ऑपरेशन टाइगर

(d) ऑपरेशन मेलन

28. कौन सा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भारत में "परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम" के तहत तपेदिक (TB) स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य बना?

(a) कर्नाटक (b) जम्मू और कश्मीर

(c) उत्तराखंड (d) पुडुचेरी

29. प्रधानमंत्री पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है?

(a) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(b) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(c) वित्त मंत्रालय

(d) शिक्षा मंत्रालय

30. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में उल्लिखित सभ्य कार्य और आर्थिक विकास (एसडीजी 8) के वैश्विक रुझानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. वैश्विक कार्यबल का आधे से अधिक अनौपचारिक रूप से कार्यरत है।

2. युवा बेरोजगारी दर वयस्क बेरोजगारी दर के लगभग बराबर है।

3. एसडीजी 8 के अंतर्गत ट्रैक किए गए आधे संकेतक स्थिरता या गिरावट दर्शाते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

31. निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रूज़ मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच सही अंतर करता है?

(a) क्रूज़ मिसाइलें तेज़ होती हैं और परवलयिक पथ का अनुसरण करती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें धीमी होती हैं और कम ऊँचाई पर उड़ती हैं।

(b) बैलिस्टिक मिसाइलें पूरी उड़ान के दौरान निर्देशित होती हैं, जबकि क्रूज़ मिसाइलें बिना निर्देशित होती हैं।

(c) क्रूज़ मिसाइलें कम ऊँचाई पर उड़ती हैं और पूरी उड़ान के दौरान निर्देशित होती हैं; बैलिस्टिक मिसाइलें एक ऊँचे चाप का अनुसरण करती हैं और केवल प्रारंभिक चरणों में निर्देशित होती हैं।

(d) दोनों प्रकार की मिसाइलें रडार के नीचे उड़ती हैं और प्रक्षेपण के बाद पूरी तरह से स्वायत्त होती हैं।

32. हाल ही में चर्चा में रही सीन नदी किस देश में स्थित है?

(a) इंडोनेशिया (b) ऑस्ट्रेलिया

(c) चीन (d) फ्रांस

33. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) किस मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है?

(a) शिक्षा मंत्रालय (b) शहरी विकास मंत्रालय

(c) गृह मंत्रालय (d) जनजातीय कार्य मंत्रालय

34. किस संगठन ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज (UHC PEERS) नेटवर्क लॉन्च किया है?

(a) एशियाई विकास बैंक (ADB)

(b) विश्व बैंक

(c) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

(d) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)

35. भारत का पहला तटीय-आधारित ताप विद्युत संयंत्र, एनटीपीसी सिम्हाद्रि, किस राज्य में स्थित है?

(a) कर्नाटक (b) गुजरात

(c) आंध्र प्रदेश(d) ओडिशा

36. पांडुलिपि विरासत पर भारत के पहले वैश्विक सम्मेलन का शीर्षक क्या है?

(a) भारत की पांडुलिपियाँ: एक सांस्कृतिक विरासत

(b) भारत के प्राचीन ज्ञान की पुनर्खोज

(c) पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना

(d) वैदिक ज्ञान पर वैश्विक संगोष्ठी

37. किस संगठन ने "फ्रंटियर्स 2025: द वेट ऑफ टाइम" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है?

(a) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

(b) विश्व बैंक

(c) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)

(d) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

38. भारत का पहला जल प्रौद्योगिकी पार्क 'एक्वा टेक पार्क' का उद्घाटन कहाँ किया गया?

(a) ओडिशा (b) सिक्किम

(c) असम (d) कर्नाटक

39. हाल ही में भारत के तेजस लड़ाकू विमानों के लिए दिया गया GE-F404 इंजन किस देश द्वारा आपूर्ति किया गया था?

(a) रूस (b) फ्रांस

(c) जर्मनी (d) संयुक्त राज्य अमेरिका

40. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार, भारत की वर्तमान वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग क्या है?

(a) 65वाँ (b) 75वाँ

(c) 77वाँ (d) 84वाँ

41. ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संगठन ने बीमा सखी योजना शुरू की?

(a) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)

(b) नीति आयोग

(c) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(d) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

42. हाल ही में रिपोर्ट किया गया लम्पी स्किन डिजीज (LSD) मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समूह को प्रभावित करता है?

(a) पक्षी (b) स्तनधारी

(c) मवेशी (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

43. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बन गया है?

(a) राजस्थान (b) गुजरात

(c) उत्तर प्रदेश (d) मध्य प्रदेश

44. हाल ही में खबरों में रहा साइरोस द्वीप किस देश में स्थित है?

(a) फ्रांस (b) ग्रीस

(c) स्पेन (d) इंडोनेशिया

45. भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है?

(a) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)

(b) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

(c) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

46. निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र के संबंध में केंद्रीय तर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?

(a) विश्वविद्यालयों को एकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विचारधाराओं के साथ जुड़ना चाहिए।

(b) असहमति को दबाने से स्थिरता सुनिश्चित होती है और शैक्षणिक संघर्ष कम होता है।

(c) घरेलू शैक्षणिक स्वतंत्रता से अधिक वैश्विक प्रतिष्ठा मायने रखती है।

(d) बौद्धिक स्वतंत्रता और असहमति एक जीवंत लोकतंत्र की नींव हैं।

47. POSH अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) में निम्नलिखित में से कौन-सी अनिवार्य विशेषता नहीं है?

(a) पीठासीन अधिकारी एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी होनी चाहिए।

(b) सभी सदस्य संगठन के भीतर से ही होने चाहिए।

(c) कम से कम एक सदस्य किसी NGO से या यौन उत्पीड़न विशेषज्ञ से होना चाहिए।

(d) समिति में महिलाओं का न्यूनतम 50% प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

48. राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंडा चोलपुरम की स्थापना मुख्यतः इस उद्देश्य से की थी:

(a) अपने उत्तराधिकारी के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में

(b) अपने समुद्री व्यापार प्रभुत्व का जश्न मनाने के लिए

(c) गंगा की ओर अपने सफल उत्तरी सैन्य अभियान की स्मृति में

(d) तंजावुर के स्थान पर एक शैव धार्मिक राजधानी स्थापित करने के लिए

49. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित नीतिगत साधनों पर विचार करें:

1. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी)
2. व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ)
3. हरित ऊर्जा मुक्त पहुँच नियम

उपर्युक्त में से कौन-से बाज़ार-आधारित तंत्र हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

50. हाल ही में एफएटीएफ की रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा आतंकवादी समूहों द्वारा अपनी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक नया स्वीकृत तरीका है?

(a) स्विफ्ट कोड के माध्यम से बैंकिंग

(b) केवल मस्जिदों के माध्यम से दान

(c) धन हस्तांतरण के लिए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग

(d) पोस्टल मनीऑर्डर

RACE IAS

# RACE IAS®

Since 2010

# UPSC MAINS TEST SERIES - 2025

| Test No. | Paper | Date | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | Sectional | 10 June, 25 | Polity + Governance+ IR |
| 2 | Sectional | 14 June, 25 | Indian & World History + Art & Culture |
| 3 | Sectional | 21 June, 25 | Geography + Environment & Ecology + Society + DM |
| 4 | Sectional | 28 June, 25 | Science & Tech. + Economy + Internal Security |
| 5 | Sectional | 05 July, 25 | Qualifying paper (Hindi) |
| 6 | Full Length | 12 July, 25 | Qualifying paper (English) |
| 7 | Full Length | 19 July, 25 | Essay (All three Section) |
| 8 | Full Length | 26 July, 25 | GS Paper 1 (Full Syllabus) |
| 9 | Full Length | 02 Aug., 25 | GS Paper 2 (Full Syllabus) |
| 10 | Full Length | 07 Aug., 25 | GS Paper 3 (Full Syllabus) |
| 11 | Full Length | 16 Aug., 25 | GS Paper 4 (Full Syllabus) Ethics Integrity & Aptitude |

**COMMENCING FROM 10, JUNE 2025**

**REGISTRATION OPEN**

## LUCKNOW & KANPUR

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

## 7388114444, 9044241755

www.raceias.com | /raceiaslucknow | YouTube/raceiaslko | Follow us on :

# RACE IAS

**A Leading Institute for Civil Services Examination**

## PRACTICE IS THE KEY TO SUCCESS

# UPSC/UP PCS

## मेन्स / प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज

**ENROLL NOW**

**OFFLINE / ONLINE BATCH**

**English / Hindi Medium**

## सामान्य अध्ययन (GENERAL STUDIES)

**04 अगस्त से नया बैच प्रारंभ**

Days Classes **FREE**

**ADMISSION OPEN**

**मेंटरशिप प्रोग्राम**

- मेन्स PYQ
- Focus on Answer writting skill
- Current Affairs

**Special Mentorship Programme for Mains Examination**

**Online Live Classes through RACE Mobile App**

*Our Centers*

| Aliganj | Indira Nagar | Alambagh | Ashok Nagar |
|---|---|---|---|
| Lucknow (U.P.) | Lucknow (U.P.) | Lucknow (U.P.) | Kanpur (U.P.) |
| Mob.: 7388114444 | Mob.: 9044137462 | Mob.: 8917851448 | Mob.: 9044327779 |

अभी डाउनलोड करें - RACE IAS मोबाइल ऐप

GET IT ON Google Play | Available on Windows Store

Follow us on :

www.raceias.com